Tni आवाज़

राजस्थान की राजनीति

E-mail: tniawaz.news@gmail.com
आपकी आवाज के साथ....
RAJHIN/2012/43137

HP NEWS हिन्दुस्तान की आवाज
हिन्दुस्तान पत्रिका
HINDUSTAN KI AWAZ

जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, टोंक, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, कोटा, सवाईमाधोपुर से प्रसारित

www.hpnews.in/www.tniawaaz.in | जयपुर, गुरूवार 03 अप्रैल, 2025 | वर्ष: 2 | अंक: 154 | पृष्ठ: 8 | मूल्य: 2.00 रू.

डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक, गर्मी के मौसम में आमजन को सुनिश्चित हो निर्बाध विद्युत आपूर्ति

विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स उठाएं प्रभावी कदम - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत् मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही, डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम्स) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करें, जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया।

पीएम कुसुम योजना में लाएं गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ए तथा सी कम्पोनेन्ट्स मील का पत्थर साबित होंगे। इन कम्पोनेंट में अपेक्षित गति लायी जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में आरडीएसएस योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स इस योजना की प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। जो कॉन्ट्रेक्टर्स योजना के कार्यों को संपादित करने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

मुफ्त बिजली योजना को त्वरित क्रियान्वित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए निःशुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना की त्वरित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लंबित कृषि कनेक्शन्स को प्राथमिकता से जारी करें

शर्मा ने डिस्कॉम्स को लंबित घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शन शीघ्र जारी करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लंबित कृषि कनेक्शन्स को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। डिस्कॉम्स के अधिकारी प्रतिदिन कृषि कनेक्शन जारी करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेंजे। मुख्यमंत्री ने पीएचईडी कनेक्शनों को जारी करने की स्थिति, 33 और 11 केवी जीएसएस के निर्माण और खराब ट्रांसफार्मर के रिप्लेसमेंट की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स चैयरमेन सुआरती डोगरा, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल, अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा उपस्थित रहे। वहीं सभी जिलों के कलक्टर वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

खबर संक्षेप

पाथर प्रतिमा विस्फोट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता। वेस्ट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पाथर प्रतिमा में

हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को अरेस्ट कर लिया है। इस विस्फोट में आठ लोग मारे गए थे। मुख्य आरोपी चंद्रकांत बानिक पटाखा निर्माण इकाई का मालिक है। इस सिलसिले में यह पहली गिरफ्तारी है।

दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर भिड़ गई महिला

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स के बीच लड़ाई-बहस के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया

पर वायरल होते रहते हैं। वायरल वीडियो में महिलाएं मेल पैसेंजर से सीट के लिए झगड़ा करते दिख रही हैं। जनकपुरी वेस्ट के पास ब्लू लाइन पर हुई, जहां बैठा शख्स महिलाओं के ग्रुप के साथ बहस में उलझ गया।

दिल्ली के द्वारका में धू-धू कर जल गईं 11 कारें

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर-24 इलाके में बुधवार तड़के एक गैराज धू-धू कर जल गया। 11

कारें जलकर खाक हो गईं। एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां भेजी गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि लगभग 3बजे धुल सिरस स्थित एक गैराज में आग लगने की सूचना मिली।

लालू यादव पटना से दिल्ली रेफर

पटना। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। आरजेडी सुप्रीमो

लालू यादव को अचानक पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार सुबह से ही लालू यादव की तबीयत खराब थी। यादव को पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां से दिल्ली रेफर कर दिया गया।

वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर भड़के अनुराग, पहले का 'काला इतिहास' ही खोल दिया

यहां मुगलिया फरमान नहीं चलेगा, बाबा साहेब का संविधान चलेगा, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं

इस के अंतिम संस्कार का समय आ गया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

वक्फ बिल को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। जहां सत्तापक्ष इसे गरीबों और मुस्लिम समुदाय के हित में बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने और सत्ताधारी दल के फायदे का हथियार करार दिया है। चर्चा में शामिल होते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ को बदलने के वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कह दिया जाता था कि यह वक्फ की जमीन है, वह जमीन वक्फ की हो जाती थी। लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि खाता न बही, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। ये विधेयक नहीं एक उम्मीद है। ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। यह साफ संदेश है कि मोदी राज में देश का कानून ही चलेगा। यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहां मुगलिया फरमान नहीं चलेगा, बाबा साहेब का संविधान चलेगा।

> ठाकुर ने कहा कि वक्फ को बदलने के वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। पहले कह दिया जाता था यह वक्फ की जमीन है।

वक्फ को बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि ये अत्याचार-भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया

मात्र 200 लोगों के हाथ में वक्फ की संपत्ति

भाजपा सांसद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम और महिला विरोधी है। मात्र 200 लोगों के हाथ में वक्फ की संपति है। कांग्रेस के समय बना वक्फ कानून

ये बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ

ठाकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह बिल कांग्रेस पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मकसद मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपदा का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपारदर्शी और गैरजिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा सम्राज्य बनाया, जहां पर इसको अपने वोट बैंक का एटीएम बना दिया। देश ने 1947 में एक विभाजन देखा है, आज फिर से हम जमीन जेहाद के नाम पर विभाजन नहीं होने देंगे।

अखिलेश ने कहा

वक्फ बिल को नाकामी पर पर्दा बताया

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल नाकामी पर पर्दा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। रातोंरात नोटबंदी का फैसला लिया। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल मुसलमानों के खिलाफ है।

कर्नाटक सरकार पर करोड़ों कमाने का दावा किया, लालू ने भी आरोप लगाया था

ठाकुर ने कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि कांग्रेस सरकार वक्फ अधिनियमों के जरिए हर साल 440 करोड़ रुपए कमा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या आपने किसी मस्जिद या मदरसे का पैसा लिया? आपको इसका जवाब देना चाहिए. ठाकुर ने कहा कि वक्फ के नाम पर कई लोगों की जमीन छीनी गई है। लालू यादव ने भी आरोप लगाया था कि पटना के डाकबंगले की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली थी।

भाजपा के रविशंकर बोले

वक्फ बोर्डों में पिछड़े मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं

लोकसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष संविधान उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, लेकिन अगर आप कानून के किसी हिस्से का उल्लेख करते हैं तो पूरे तथ्य का उल्लेख करें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुरूप है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्डों में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। यह खुद अपने आप में संविधान में मिले अधिकारों का उल्लंघन है।

ललन ने दिखाया आईना

आपने जो पाप किया था पीएम पारदर्शिता ला रहे

जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में विधेयक का समर्थन किया है। सिंह ने कहा कि माहौल बनाया जा रहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी है। गलत जानकारी दे रहे। यह मुसलमान विरोधी है, कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। सिंह ने कहा कि मोदीजी को लोग कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में आपने जो पाप किया था, उसे समाप्त करके पारदर्शिता लाने का काम किया है।

अखिलेश की टिप्पणी पर शाह का तंज

आप 20-25 साल अध्यक्ष रहेंगे

अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक ये पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के 10-12 करोड़ पंजीकृत सदस्य हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप 20-25 साल अध्यक्ष रहेंगे। अमित शाह की टिप्पणी पर अखिलेश यादव भी मुस्कराते हुए नजर आए।

ओवैसी ने फाड़ी कॉपी

बिल को बताया असंवैधानिक

बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात को रखते हुए बिल की कॉपी को फाड़ दिया। यह असंवैधानिक बिल है।ओवैसी ने कहा कि सरकार ये जो कानून बना रही है वो आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। भाजपा देश में झगड़े पैदा करना चाहती है। कल को कलेक्टर कहेगा यह सरकार की संपत्ति है और वहां पोस्टर चिपका देगा। मस्जिदें बंद हो जाएंगी।

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ का बड़ा दावा

यह किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं

भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि विधेयक मुसलमानों के कल्याण के लिए पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि ऐसा नहीं लगा रहा कि संसद में पेश किया गया विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है।

हमारे नेता पर हमला कर रहे : वेणुगोपाल

ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वे सदन को गुमराह कर रहे हैं और हमारे नेता पर हमला कर रहे हैं। वे अपनी जातिवादी सोच सामने ला रहे हैं। ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने किसी की जाति का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने अपने असली रंग दिखा दिए। आप पारदर्शिता नहीं चाहते।

रेलवे के मुद्दे पर लोकसभा में भाजपा-सपा के बीच नोकझोंक

बोले रेल मंत्री, नई फेंसिंग लगाने से कम होंगी रेलवे ट्रैक पर होने वाली जानवरों की दुर्घटनाएं

▶▶ नई दिल्ली

लोकसभा में बुधवार को रेलवे के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ देर के तक हल्के-फुल्के अंदाज में की जा रही टीका टिप्पणियों का सिलसिला देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अवधेश प्रसाद ने रेल लाइनों को पार करते वक्त ट्रेन से टकराकर मारे जा रहे जानवरों का मुद्दा उठाया। तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, इस प्रश्न को पूछने के लिए अवधेश जी के नाम की अनुशंसा

अखिलेश जी ने की है। इसका जवाब देते हुए अखिलेश बोले, अध्यक्ष जी अब देखिएगा सांसद महोदय सरकार से ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि जिसका जवाब ही नहीं मिलेगा? लेकिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना जवाब कुछ इस तरह से दिया कि विपक्षी दल चाहकर भी कुछ नहीं कह सका।

नए डिजाइन की फेंसिंग से होगा बचाव

उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर जानवरों के मारे जाने का मामला सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन इसका समाधान निकालने के लिए हमने देश में एक नए डिजाइन की फेंसिंग लगाना शुरू किया है। अभी इसे 900 किलोमीटर में लगाया जा चुका है, जिसकी वजह से ट्रेन के आगमन पर जानवरों के रेलवे ट्रैक पार करने से होने वाली दुर्घटनाएं न के बराबर यानी शून्य तक जा पहुंची हैं। प्रयोग सफल रहा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। कन्नौज में रेल लाइन का डिजाइन बदला गया है।

दंगे में 3 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या, सभी बरी

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तीन ब्रिटिश नागरिकों और उनके

भारतीय चालक की हत्या के आरोपी 6 लोगों को 2015 में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और समीर जे दवे ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त पाया, तथा सत्र न्यायालय द्वारा जारी फैसले को बरकरार रखा।

'शिशु वाटिका' पहल का शुभारंभ

माझी ने मध्याह्न भोजन परोसा

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के एक सरकारी स्कूल में नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत राज्य के सभी स्कूलों में 5-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा का विस्तार करने के लिए 'शिशु वाटिका' पहल के शुभारंभ के दौरान छात्रों को मध्याह्न भोजन परोसा।

अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक, अवैध खनन पर राज्य सरकार सख्त, आकस्मिक संयुक्त अभियान से होगी अब अवैध खनन पर रोकथाम, कार्मिक राज्यहित को दें सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यालय स्तर पर भी संयुक्त टीम बनाकर करें औचक निरीक्षण

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें तथा राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए।

अवैध खनन के खिलाफ हो प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करे जिससे आमजन को राहत पहुंचे। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें।

ड्रोन सर्वे से करें पूरी निगरानी

श्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही, अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें जिससे अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में गति लाई जा सके।

एम-सेंड को दिया जाए प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सेंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रुप में एम-सेंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकांत ने अवैध खनन के संभावित खनिज एवं संवेदनशील जिले, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान, गत पांच वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही, संस्थागत तंत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों तथा जिलों की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण श्री प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री दिनेश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिजीत बनर्जी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण बैठक में जुड़े।

निजीकरण के विरोध में विद्युतकर्मियों का प्रदर्शन, एसडीएम को दिया ज्ञापन

विद्युतकर्मियों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी के बीच किया प्रदर्शन

निजीकरण पर रोक नही लगाने पर विद्युतकर्मियों ने दी आन्दोलन की चेतावनी

राजस्थान की राजनीति

नदबई। विद्युत निजीकरण के विरोध में बुधवार को राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में विद्युतकर्मियों ने नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। वही, विद्युत निजीकरण नही रोकने पर प्रदेशस्तरीय आन्दोलन करने की चेतावनी दी। बाद में एसडीएम गंगाधर मीणा ने विभागीय उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इससे पहले विद्युतकर्मियों ने नदबई एसडीएम कार्यालय के समक्ष नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए विद्युत निजीकरण का जमकर विरोध किया। वही, प्रदेश सरकार पर विद्युत निजीकरण होने से विद्युतकर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन देते हुए निजीकरण रोकने व निजीकरण नही रोकने पर प्रदेशस्तरीय आन्दोलन करने को कहा। इस दौरान सहायक अभियंता शिवसिंह मीणा, कनिष्ठ अभियंता कृष्णवीर, एआरओ पीयुष दुबे, इंटक अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह कुंतल, कन्हैयाराम, लोकेश शर्मा, वीरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, प्रेमी जाट, हेमन्त सिंह आदि मौजूद रहे।

आग लगने से पांच बीघा जमीन की गेहूं फसल जलकर स्वाहा

नगर पालिका दमकल की सहायता से पाया आग पर काबू

शॉर्ट सर्किट से लगी फसल में आग, नदबई क्षेत्र के गांव अरोंदा का मामला

राजस्थान की राजनीति

नदबई। नदबई क्षेत्र के गांव अरोंदा में स्थित एक खेत में आग लगने के चलते करीब पांच बीघा जमीन की गेहूं फसल जलकर बर्बाद हो गई। इससे पहले ग्रामीणों ने निजी डीपबोर से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में नदबई नगर पालिका दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लेकिन, इससे पहले खेत में रखी फसल जलकर स्वाहा हो गई। विभागीय सूत्रों की मानें तो अरोंदा निवासी पीडित, पवन सिंह पुत्र खिल्लाराम ने अपनी गेहूं फसल काटकर खेत में एकत्रित कर रखी। देर रात अचानक विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से फसल में आग लग गई। समीपवर्ती लोगों ने निजी डीपबोर की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में नगर पालिका दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लेकिन, इससे पहले गेहूं फसल जलकर बर्बाद हो गई। इस संदर्भ में समाचार लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नही हुआ।

गांव कबई में कमरे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम

किसान के घर से सरसों और बाजरे के कट्टे किऐ चोरी

पीडित ने कराया थाने में मामला दर्ज

राजस्थान की राजनीति

नदबई। क्षेत्र के गांव कबई में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने एक कमरे का ताला तोड़कर वहां रखी सरसों और बाजरे की बोरियां चोरी कर लीं। इस संबंध में गांव कबई निवासी पीड़ित अजबसिंह पुत्र बाबूलाल ने मंगलवार शाम को नदबई थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अजबसिंह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि, गांव के ही रहने वाले बौबी पुत्र राकेश और मनीष पुत्र अतरसिंह जाटव सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने कमरे का ताला तोड़कर वहां से छह बोरी सरसों, एक कट्टा सरसों और दो कट्टा बाजरा चोरी कर लिया। जब पीड़ित को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने आरोपियों से तकादा किया, तो आरोपियों ने उसे खुलेआम धमकी दी। इससे पीड़ित डर और असुरक्षा की भावना से घिर गया। आखिरकार, उसने मंगलवार शाम को नदबई थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कृषि विभाग ने तारबंदी योजना के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

अब एक जगह न्यूनतम दो बीघा जमीन वाले

किसानों भी मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ

कृषि विभाग से तारबंदी पर किसानों को मिलेगा 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान

राजस्थान की राजनीति

दौसा (विष्णु आशीर्वाद)। कृषि विभाग ने कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष विभाग ने न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में शिथिलता दी है। अब काश्तकार एक जगह न्यूनतम आधा हैक्टेयर (दो बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगे। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीना ने बताया कि किसान कड़ी मेहनत व लागत लगाकर फसल और सब्जियां पैदा करते हैं परंतु नील गाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फसलों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से खेतों की कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए है। पूर्व वर्षो में तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था परन्तु इस वर्ष विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में शिथिलता देते हुए व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसान एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (02 बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगे। जिले के सभी सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र के पात्र एवं इच्छुक किसानों से तारबंदी योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाने के आवश्यक निर्देश प्रदान किया गया है।

किसानों को इस तरह मिलेगा अनुदान

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीना ने बताया कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु समूह में यदि न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा पक्की) भूमि में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि के हिसाब से प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56000 की अनुदान राशि मिलेगी एवं व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (2बीघा पक्की) भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48,000 रुपये एवं सामान्य किसानों को 40,000 रुपये का अनुदान तारबंदी पर कृषि विभाग के माध्यम से दिया जाएगा।

राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें

योजना के लिए इक्छुक एवं पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी एवं जनाआधार कार्ड,लघु-सीमान्त प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ई मित्र केंद्र या स्वयं के द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें ताकि पहले आओ,पहले पाओ'के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।

इस प्रकार करनी होगी खेतों की कांटेदार-चैनलिंक तारबंदी

किसान व्यक्तिगत या समूह में खेतों की तारबंदी करते समय 15 फ़ीट की दूरी पर खम्भे लगाए व 5 कांटेदार वायर आड़े व 2 कांटेदार वायर क्रॉस लगाए या चैनलिंक जाल भी लगा सकते हैं। लोहे व सीमेंट के खम्बे की सुरक्षा के लिए भूमि में पीसीसी भी करना जरूरी है। तारबंदी पर व्यय राशि के समस्त बिल किसानों को उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य पूर्ण होने के उपरांत सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा व अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

भाई की ससुराल में युवक ने खुद के सिर में मारी गोली, मौत

राजस्थान की राजनीति

दौसा। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के खटीकान मोहल्ले में बीती रात अपने भाई के ससुराल में आए एक युवक ने देसी कट्टे से खुद को गोली मार ली घायल अवस्था में परिजन युवक को दोसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस सीओ रवि प्रकाश शर्मा, कोतवाल सुधीर उपाध्याय,डीओ जवान सिंह मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे और सापेक्ष जुटे । मौके पर स्नस्रु टीम को बुलाकर भी सापेक्ष जुटाए गए । पुलिस के द्वारा घटना का अनुसंधान किया जा रहा है ।बताया जा रहा है कि मृतक विष्णु खटीक दिल्ली का रहने वाला है और अपने भाई के ससुराल दोसा में मंगलवार को आया था भाई की ससुराल में ही किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई ऐसे में युवक ने खुद को सिर में गोली मार ली । मौके पर ही मृतक का भाई भी मौजूद था उसने मृतक को रोकने की खूब कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। विष्णु खटीक को घायल होने पर उसे जिला अस्पताल ले जाएगा जहां चिकित्सक ने जांच के बाद विष्णु खटीक को मृत घोषित कर दिया। शव को दौसा जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया । कोतवाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना ने उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा का जताया आभार, छात्रवृत्ति एवं स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत आवेदन में संशोधन की तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ाई, आवेदन में संशोधन के लिए पात्र वंचित विद्यार्थियों को मिलेगा एक और अवसर

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए स्कूटी एवं छात्रवृत्ति वितरण से पात्र विद्यार्थी फार्म में संशोधन नहीं होने से वंचित नहीं रह जाए। इस स्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर विद्यार्थियों की समस्या से अवगत करवाया एवं विद्यार्थियों को एक और अवसर प्रदान करने का आग्रह किया।

भड़ाना के अनुरोध पर उपमुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन के लिए अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे वे विद्यार्थी जिनके आवेदन में त्रुटियाँ रह गई थीं। अब वे अपने फॉर्म को सही कर सकेंगे और योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उच्च शिक्षा आयुक्तालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं स्कूटी वितरण योजना के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में निर्देश जारी करते हुए विद्यार्थियों के आक्षेप पूर्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 की गई। इसमें वर्ष 2024–25 के लिए काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, सहरिया छात्र-छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले अनेक छात्र-छात्राओं का आवेदन पत्र में ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने के कारण संशोधन नहीं किया जा सका। इससे अंतिम वरीयता सूची में नाम नहीं जुड़ सका। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो जाने के कारण ये विद्यार्थी संशोधन करने से वंचित रह गए थे।

भड़ाना ने इस निर्णय के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंधत्व निवारण सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी आयोजित

राजस्थान की राजनीति

भरतपुर। कृषि महाविद्यालय भुसावर में अंधत्व निवारण सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉ. उदय भान सिंह ने कहा कि दृष्टि के बिना विश्व सूना है। भारत में 10 मिलियन लोग अंधेपन से पीडित हैं तथा दुनियाभर में अंधे लोगों की संख्या 37 मिलियन है। उन्होंने बताया कि अंधेपन के मुख्य कारण ट्रेकोमा, मोतियाबिन्द, विटामिन ए की कमी, कुपोषण और दान की गयी आंखो की कमीं है। अंधता निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रूबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निया दान के लिए लोगों में जागरूकता, नेत्र देखभाल का ज्ञान, नेत्र संबंधी बीमारियों तथा मोतियाबिन्द का समय पर उपचार तथा दृष्टि दोषों के लिए उचित चश्मा की निशुल्क व्यवस्था होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में आँखों से जुडी समस्याएँ बढ जाती हैं, जिससे आँखों में जलन और दीर्घकालिक नुकसान का जोखिम बढ़ता है। उन्होंने नेत्रों की नियमित जाँच कराने तथा आँखों की चोटों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी। ग्लूकोमा को दृष्टि का मूक चोर कहा जाता है और यह अंधेपन का कारण बन सकता है। दृष्टि ईश्वर का एक अनमोल उपहार है, इसे बचायें।

विचार गोष्ठी में डॉ. एस.एल. यादव व डॉ. बी. एल. जाखड ने भी विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर समस्त कॉलेज स्टॉफ व विद्यार्थी उपस्थित थे।

गर्मी से बचाव के लिए आमजन बरतें सावधानी - डॉ. गौरव कपूर

गर्मी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से की अपील

राजस्थान की राजनीति

भरतपुर। जिले में बढ रही गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों बढ़ती गर्मी से आमजन चपेट में आ सकते है, खासकर हाई रिस्क वाले लोगो को खास ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं गर्मी के मौसम में जिले के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रो पर विशेष सावधानी बरतने के लिए विभाग ने निर्देश दिए है। सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए कि राज्य व जिला स्तर से प्राप्त निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना की जावे। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट एवं पूर्वानुमान अनुसार आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। सभी अस्पतालों में रोगियों के उपचार के साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ओआरएस, ड्रिप सेट, ब्लीचिगं पाउडर सहित अन्य आवश्यक दवाईयां रखी जावे। उन्होंने कहा कि गर्मी से होने वाली बीमारियो जैसे उल्टी, दस्त पीलिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की सतर्कता से निगरानी रखें एवं उपचार उपलब्ध करवाएं। विभागीय कार्मिक अपने कार्यक्षेत्र में आमजन को गर्मी से बचाव के बारे में जानकारी दें तथा कार्यक्षेत्र में रेपिड रेस्पांस टीम एवं नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहे।

लक्षण– सीएमएचओ ने बताया कि शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण में सिर का भारीपन व अत्याधिक सिरदर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, जी मिचलना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढना, पसीना आना बंद होना, मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास का लगना व बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि लक्षण आने लगते है। तो उसे तत्काल निकट की चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए।

जरूरी है सावधानी– सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने आमजन से गर्मी के चलते एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होने कहा कि जहॉ तक सम्भव हो धूप में न निकले, धूप में शरीर पूर्ण तरह से ढका हो। आमजन जब भी बाहर निकले, छाता व पानी आदि की व्यवस्था अनुरूप घर से निकलें। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपडो का उपयोग करे। बहुत अधिक भीड व गर्म घुटन भरे कमरों से बचे। बिना भोजन किए बाहर न निकले। गर्दन के पिछले भाग कान एवं सिर को गमछे या तोलिये से ढक कर ही जरूरी होने पर बाहर निकले। गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिए एव पेय पदार्थो जैसे नीबू पानी, नारियल पानी, जूस आदि का प्रयोग करे। लू तापघात से प्रायः हाई रिस्क श्रेणी वाले लोग जैसे कि कुपोषित बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाए व शुगर, बीपी आदि के मरीज जल्दी प्रभावित होते है। इन्हें बाहर न निकलने दे व इनका विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर तत्काल 108 को कॉल करें या नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर लेकर जाए। नरेगा अथवा श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवं पानी का पूर्ण प्रबन्ध रखा जावे, ताकि श्रमिक छायादार स्थानों पर विश्राम कर सकें।

ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई आज

राजस्थान की राजनीति

भरतपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार 3 अप्रैल को जिले की सभी ग्राम पंचायतो में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा ।

चलती बाइक से गिरी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला

सर में गंभीर चोट आने के चलते भरतपुर किया रेफर

पति के साथ नगर से आ रही थी बुजुर्ग महिला

राजस्थान की राजनीति

नदबई। नगर सड़क मार्ग पर गांव रौनीजा के पास बुधवार दोपहर को बाइक से असंतुलित होकर गिरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल महिला को नदबई के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे भरतपुर रेफर कर दिया।

108 एंबुलेंस ईएमटी सीताराम प्रजापत ने बताया कि, गांव खेड़ी देवी सिंह निवासी अमरती देवी(60) अपने पति सुखचंदी के साथ बाइक पर सवार होकर नगर से नदबई आ रही थीं। दोपहर के समय जैसे ही वे गांव रौनीजा के पास पहुंचे, तो अचानक अमरती देवी असंतुलित होकर बाइक से नीचे गिर पड़ीं। चलती बाइक से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसा होते ही सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एंबुलेंस को घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस के ईएमटी सीताराम प्रजापत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल महिला को नदबई के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देकर भरतपुर रेफर कर दिया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद ईकाई (भारत) द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित

तराक मंगेश आरोलेकर को गोवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

परिषद के सेंट्रल डायरेक्टर लक्ष्मण लोहाना मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में की शिरकत

राजस्थान की राजनीति

गोवा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद ईकाई (भारत) द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तराक मंगेश आरोलेकर को गोवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया । यह कार्यक्रम 2 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी की अनुशंसा पर सेंट्रल डायरेक्टर लक्ष्मण लोहाना मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गोवा के पंजी में यह कार्यक्रम किया गया लोहान ने बताया की नए अध्यक्ष के साथ मिलकर हमारा प्रयास रहेगा स्वच्छ गोवा स्वस्थ गोवा समृद्ध गोवा के देश के प्रधानमंत्री एवं गोवा के मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने की पूरी कोशिश की जाएगी यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं एक पेड़ मां के नाम मोदी जी की योजना को आम जनता तक पहुंचाने आम जनता युवाओं को प्रदूषण के प्रति अवेयरनेस कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा! कार्यक्रम का नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में सिरोही एवं जालोर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल की अध्यक्षता में बुधवार को आत्मा सभागार में सिरोही एवं जालोर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीएचईडी मंत्री ने दोनों जिलों में पेयजल की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में संभावित स्थिति की जानकारी ली तथा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने पेयजल प्रबंधन के लिए गंभीरता से कार्य करने तथा पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या न आए ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जलदाय मंत्री ने आमजन द्वारा प्रस्तुत पेयजल सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण करने तथा पेयजल प्रबंधन और वितरण तंत्र को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने क्षेत्रवार पेयजल प्रबंधन की जानकारी ली तथा पेयजल स्त्रोतों व विकल्पों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आमजन को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने अधिकारियों को सरकार की मंशानुरूप कार्य करने तथा जल जीवन मिशन का कार्य समय पर पूर्ण करने व गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 व अन्य विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की व आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जलदाय मंत्री ने हैंडपंप, बावडी एवं कुओं का मरम्मत व मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा न आए इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की क्रियान्विति समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मौजूद आबू-पिंडवाडा विधायक समाराम गरासिया व रानीवाडा विधायक रतन देवासी ने भी क्षेत्रवार पेयजल आपूर्ति की समस्या एवं प्रोजेक्ट्स संबंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया जिस पर पीएचईडी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण की बात कही तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग व पूर्ण कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए।

आस्था से भरपूर बल्लभगढ की देवी माता मन्दिर

4 अप्रेल से देवी माता मेला शुभारम्भ , 5 को राष्ट्रीय कुश्ती दंगल

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम होंगे मुख्य अतिथि

मन्नू मीणा - कृष्णा मीना ने कराई मेला की शुरूआत

राजस्थान की राजनीति

हलैना। अरावली पर्वत मालाओं के चोटी पर गांव बल्लभगढ स्थित देवी माता मन्दिर आस्था से भरपूर है , जिसका निर्माण भरतपुर रिसायत के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने साल 1729 में क्षेत्र के सर्व समाज का सहयोग लेकर कराया। यहां मेले की शुरूआत साल 1912 में गांव के निवासी सगे दो भ्राता मन्नू मीणा और कृष्णा मीणा ने कराई , तभी से यहां प्रतिसाल मेला लगता आ रहा है। प्रत्येक महिना की सप्तमी-अष्ठमी को लघु मेला तथा साल में एक बार विशाल मेला लगता है। वैसे समय-समय पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते रहते है। सभी मेले और धार्मिक कार्यक्रम में गांव बल्लभगढ सहित पडौसी गांव के भारी सख्यां श्रद्वालु शामिल होते है और देवी माता की पूजा-अर्चना एवं दर्शन करे है। श्रद्वालुओं की मनोकामनाएं पूरी होने पर ये परिवार व रिस्तेदारों सहित आते है और परिवार में नव शिशु के जन्म लेने एवं विवाह योग्य युवक-युवती की शादी आदि खुशी होने पर माता की जात देने तथा बच्चों का मुंडन संस्कार को यहा आते है। समय के बदलाव के साथ मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए रहट-झूले,सर्कस आते है तथा खेलकूद, कुश्ती, नौंटकी, कविसम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कराए जाते है। मेले में भारी सख्यां में भारी सख्यां में खिलौना,मिष्ठान,चाट,वस्त्र,दैनिक जीवन में काम आने वाले घरेलू सामान,श्रृंगार आदि की दुकान आती है। दुकानों से मेलार्थी व ग्रामीण जमकर खरीददारी करते है और मेले का आनन्द लेते है। बल्लभगढ की देवी माता के प्रति आस्था कायम होने पर भरतपुर रियासत के राजा-महाराजा,ठाकुर,राजनैतिक - गैर राजनैतिक संगठन के लोग आदि आ चुके है , जिनमें भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल,महाराजा जवाहर सिहं,महाराजा विजेन्द्र सिहं,महाराजा विश्वेन्द्र सिंह,राजा मान सिंह, कुँवर अरूण सिंह,दिवंगत मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया,पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव,विधायक बहादुर सिंह कोली,पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली,पूर्व सांसद रंजीता कोली आदि आ चुके है। साथ ही क्षेत्रीय प्रधान,पूर्व प्रधान,सरपचं,पूर्व सरपचं आदि शामिल होते है। जो सभी देवी माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना करते है। इस बार साल 2025 का 114 वां देवी माता मेला 4 अप्रेल से शुरू होगा,जो 5 अप्रेल तक लगेगा। जो मेला ग्राम पंचायत बल्लभगढ,मेला कमेटी तथा गांव के लोगों के सहयोग से लगता है। मेला कमेटी के संरक्षक व पूर्व सरपचं कलुआराम मीणा एवं प्रशासक प्रतिनिधी दिलीप मीणा ने बताया कि 4 अप्रेल को सुबह देवी माता मेला का ध्वजारोहण होगा,जिसके बाद पूजा-अर्चना होगी और इसी दिन अनेक प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताए होगी। दूसरे दिन 5 अप्रेल को विशाल कुश्ती दंगल होगा,जिसमें स्थानीय पहलवानों सहित देश के कई राज्यों के पहलवान भाग लेंगे। विजेता पहलवानों को ग्राम पंचायत,मेला कमेटी और गांव के लोगों के द्वारा पुरूस्कार प्रदान किए जाऐंगे। इस दिन कुश्ती दंगल के मुख्य अतिथि गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह कोली होंगे।

महारानी हंसिया के आग्रह पर हुआ निर्माण

भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल की ससुराल सलेमपुर कला में थी और उनकी पत्नी का नाम हंसिया था। जब भी महाराजा सूरजमल भरतपुर से सलेमपुर कला आते और जाते तो रास्ते में बल्लमगढ़ गांव पडता था। इस गांव में महारानी हंसिया की एक सखी थी। जो माता देवी की परम भक्त थीं। जिसने एक बार महाराजा सूरजमल,महारानी हंसिया से आग्रह कर घर रुकने का न्यौता दिया। जो उनके गांव में रुके। जिसके आदर भाव और सेवा भाव को देख कर महारानी हंसिया बेहद खुश हुई। महारानी हंसिया ने अपनी सखी से कहा कि आपकी क्या इच्छा है, हमसे जो मांगेगी वह ही मिलेगा। सखी ने माता देवी की स्थापना कराने का आग्रह किया। तब महाराजा सूरजमल ने माता देवी का मंदिर निर्माण कराने की बात स्वीकार कर ली। 1729 में माता देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। जो मंदिर गांव के पास पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया जो कई किलोमीटर दूर से लोगों को आज भी नजर आता है।

पशुपालन विभाग की बजट समीक्षा बैठक आयोजित, विभाग बजट घोषणा के कार्यो की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करे

पशुपालन मंत्री –मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का काम प्रगति पर

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बजट में स्वीकृत योजनाओं और कार्यो को शत–प्रतिशत पूरा करने के अपने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि बजट में स्वीकृत सभी कार्यो को पूर्ण करने की दिशा में अपनी कार्य योजना बनाएं। कुमावत बुधवार को पशुपालन विभाग की बजट समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य रूप से 2024-25 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर अधिकारियों से चर्चा कर संतोष व्यक्त किया कि अधिकतर बजट घोषणाएं समय पर पूरी हो गई है। साथ ही विभाग के पास कोई बिल भी लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पिछली बजट घोषणा की अनुपालना में गाय और भैंस के लक्ष्य से अधिक पंजीकरण हो गए जिसका लॉटरी निकाला जा चुका है। अब तक 42 हजार हेल्थ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं और लगभग 2 हजार पशुओं का बीमा हो चुका है। मंत्री श्री कुमावत ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए बीमा के काम में और गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष रह गए पंजीयन भी शीघ्र परा करने के निर्देश दिए। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में स्वीकृत संस्थाओं के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए श्री कुमावत ने जल्द भूमि के पट्टे प्राप्त कर इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने उन्हें इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया। नए संस्थानों में उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों के संबंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इनकी गुणवत्ता पूर्णतः सुनिश्चित की जाए। क्वालिटी से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।

मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के प्रभावी संचालन पर चर्चा करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि जिस उद्देश्य से इनकी शुरुआत की गई थी अभी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते तो कहीं दवाइयां और पशुओं को ऐसे में उचित ईलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने संबंधित कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग करते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। टीकाकरण की व्यवस्था को भी और बेहतर तथा सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।

राज्य में आयोजित पशु मेलों की व्यवस्था पर असंतोष जाहिर करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि अभी मेलों में अव्यवस्था को लेकर पशुपालकों की शिकायतें आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेले व्यवस्थित रूप से होने चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से पशु मेलों का आयोजन होना है जिसकी अनुपालना में 11 जिलों में मेलों के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गाइडलाइन भी तैयार हो गई है। इस संबंध में शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने सुझाव दिया कि मेले लगाने के राज्य स्तर पर एक मॉडल प्लान बनाया जाए और उसी के अनुरूप सभी मेले आयाजित किए जाएं।

पिछली बजट घोषणा में प्रस्तावित उष्ट्र संरक्षण एवं विकास मिशन की स्थापना निदेशालय में हो गई है। इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। मंत्री ने इस काम में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए जिससे कि ऊंटों के नस्ल सुधार और उनके संवर्द्धन के काम में तेजी आ सके। वर्ष 2025- 26 की बजट घोषणाओं पर चर्चा करते हुए श्री कुमावत ने निर्देश दिया कि सभी घोषणाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्विति ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नई घोषणा में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत दवाइयों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। श्री कुमावत ने दवाइयों का उचित इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जिससे पशुओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। बैठक में शासन सचिव पशुपालन डॉ समित शर्मा, उप शासन सचिव श्रीमती संतोष करोल, निदेशक पशुपालन डॉ आनंद सेजरा, वित्तीय सलाहकार श्री मनोज शांडिल्य, अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेश मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 5 हजार करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे बनेगें- दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री

राज्य योजना में सड़कों के लिए 17 हजार 384 करोड़ का प्रावधान

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 5 हजार करोड़ की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत् नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य, रायपुर जस्साखेड़ा, गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जायेगा । इसके साथ ही दुर्घटना सम्भावित 13 ब्लैक स्पाट्स के सुधार का कार्य भी करवाया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गड़करी का इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया है।

गत वर्ष राज्य योजना में 12620 करोड़ खर्च, अब तक का सर्वाधिक

उपमुख्यमंत्री ने कहा है की मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रही है। गत वर्ष में राज्य योजना में सड़क, पुल/आरओबी/आरयूबी निर्माण हेतु 12 हजार 620 करोड़ रूपये व्यय किये गए जो कि अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सड़क विकास के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 17 हजार 384 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। गौरलतब है कि राज्य योजना में ग्रामीण सड़क, वृहद् जिला सड़क (एमडीआर), स्टेट हाईवे सहित विभिन्न निर्माण करवाये जाते है।

सीआरआईएफ में 1300 करोड़ खर्च, अब तक का सर्वाधिक

केंद्रीय सड़क आधारभूत निधि से प्रदेश में गत वर्ष में लगभग 1300 करोड़ की लागत की सड़कों का निर्माण करवाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों एवं प्रभावी मॉनिटरिंग से सीआरआईएफ में पूर्व के वर्षों मे संचयी राशि में से राशि प्राप्त करते हुए अब तक की सर्वाधिक राशि गत वर्ष में खर्च की गई है।

नवकार महामंत्र रथ के आगमन पर जैन समाज ने पूजा अर्चना कर किया स्वागत

9 अप्रैल को होगा सामूहिक जाप

राजस्थान की राजनीति

नदबई। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) के तत्वावधान में विश्व नवकार दिवस के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जहां बुधवार को नवकार महामंत्र का रथ नदबई पहुंचा। यहां श्री जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में भव्य स्वागत एवं पूजा-अर्चना की गई।

जैन समाज के गणमान्य सदस्यों की उपस्थिति में मंदिर ट्रस्टी मोहित जैन के नेतृत्व में नवकार महामंत्र का विधिवत पूजन किया गया। इसके पश्चात रथ को मुख्य बाजार से होते हुए जैन भवन तक ले जाया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से नवकार महामंत्र का जाप किया। जैन भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवकार महामंत्र के महत्व एवं उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। जहां बताया गया कि, 9 अप्रैल को सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप होगा।

इस अवसर पर मोहन जैन पेट्रॉल पम्प वाले, दिनेश जैन कबई वाले,सुभाष जैन कबई वाले, विमल जैन, मनीष जैन, अमित जैन, राकेश मुकेश जैन पाईप वाले,राजेश जैन आटो पार्टस वाले, शिखर चंद जैन, सुशील जैन साबौरा वाले, दिनेश जैन, गर्वित जैन, नरेश जैन, पवन जैन सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

आईपीएल के आयोजन के लिए समस्त आवश्यक इंतजाम हों सुनिश्चित

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये निर्देश, जिला कलक्टर के निर्देश पर पहली बार आपात कालीन स्थिति में दर्शकों के बचाव एवं निकास के लिए कार्ययोजना तैयार

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जयपुर में आईपीएल के आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए समस्त निर्धारित मानदंडों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आईपीएल के आयोजन के संबंध में बैठक हुई।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दर्शकों के लिए निःशुल्क पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैच के आयोजन के दौरान परोसे जाने वाले भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करने एवं अस्थाई रसोईयों में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा एवं बचाव की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को स्टेडियम में एंबुलेंस मय प्रशिक्षित चिकित्सकीय दल की तैनाती करने, अलग-अलग स्थानों पर मेडिकल कियोस्क स्थापित करने, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की तैनाती करने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, दर्शकों की सघन तलाशी करने, आयोजन स्थल पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन वाहनों एवं यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, दर्शकों को नियमों की जानकारियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया। बैठक में सुरक्षा विशेषज्ञ श्री फूलचंद चौधरी ने जानकारी दी कि आईपीएल के आयोजन के लिए जिला कलक्टर के निर्देश पर पहली बार आपात कालीन स्थिति में दर्शकों के बचाव एवं निकास के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है साथ ही ब्लॉकवार निकास योजना एवं बचाव स्थल का भी चिन्हीकरण किया गया है। 24 हजार की दर्शक क्षमता वाले सवाई मान सिंह स्टेडियम में सुरक्षा के लिए लिहाज से 291 सीसीटीवी कैमरे एवं एक केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। साथ ही बैठक में जानकारी दी गई कि आईपीएल के दौरान भीड़ नियंत्रण, आपत स्थिति में बचाव कार्य सहित अन्य जरूरी व्यवस्था बनाये रखने के लिए चप्पे चप्पे पर 477 सुरक्षा गार्डो की तैनाती की जाएगी। वहीं, अमरूदों के बाग, एसएमएस इंवेस्टमेंट सेंटर, रामबाग सर्किल पर सुबोध पार्किंग सहित विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को संपूर्ण आयोजन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने सहित अन्य समस्त आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री संतोष मीणा सहित बीसीसीआई एवं राजस्थान रॉयल्स के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागरिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

चिंतन

वक्फ संशोधन न धार्मिक हस्तक्षेप, न असंवैधानिक

वक्फ संशोधन विधेयक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है और न ही असंवैधानिक है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के लिए संपत्ति प्रबंधन करना आसान हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद से देश में सियासी पारा गर्म है। सरकार ने इसे सुधारात्मक कदम बताया है तो विपक्ष इस बिल को मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर इसका तीखा विरोध कर रहा है। सरकार के मुताबिक इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन शुरू करना है। विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। दीगर बात तो यह है कि पहली बार नहीं है, जब वक्फ कानून में संशोधन हो रहा है। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया और धारा-40 जोड़ी गई। मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा-40 वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को किसी संपत्ति को अपनी जमीन घोषित करने की ताकत देता है। इसके तहत बोर्ड को रिजन टू बिलीव की ताकत मिली है। वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक वर्ष 1955 में, वर्ष 1995 में और वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन हो चुका है या कानून बदला गया है। यह संसद से हुआ है, इसलिए मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देशभर में वक्फ बोर्ड के पास आठ लाख एकड़ से अधिक जमीन है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी। 16 वर्ष में जमीन दोगुणी हो गई, कैसे?। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यूपी और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। वक्फ न्यायाधिकरणों की अभी तक कोई न्यायिक निगरानी नहीं है। इसके चलते कई दुरूपयोग की खबरें आईं। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की जमीन पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु के एक गांव थिरूचिंथुरई पर ही वक्फ ने दावा ठोक दिया, जिससे समूचे गांव के किसान परेशान हुए। वर्ष 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। केरल के एर्नाकुलम में 600 ईसाई परिवार की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। कर्नाटक के विजयपुरा में 15000 एकड़ जमीन पर राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ जमीन घोषित कर दी। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है। किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संविधान में ऐसा कानून संविधान की भावना का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे। नए वक्फ विधेयक के बाद धारा-40 खत्म हो जाएगी और वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी। कोई भी कानूनी बोर्ड धार्मिक आधार पर फैसले नहीं कर सकता है। वक्फ एक्ट में संशोधन संवैधानिक है।

अर्थव्यवस्था

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

भारत के नए वैश्विक व्यापार समीकरण

भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए सार्थक वार्ता की है। जहां एक ओर सरकार तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं हाल ही में नीति आयोग ने भारत की जीवीसी में 3 .3 फीसदी की वर्तमान हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए 13 प्रमुख सेक्टरों में सरकार से नीतिगत मदद की जरूरत रेखांकित की है। इनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑटोमोटिव सुरक्षा व ड्रोन, टेक्सटाइल, स्टील, लेदर व फुटवियर आदि शामिल हैं।

अगले 2 अप्रैल से लागू डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मार से बचने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत नए वैश्विक व्यापार समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 26 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए सार्थक वार्ता की है। जहां एक ओर सरकार तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं हाल ही में नीति आयोग ने भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में 3.3 फीसदी की वर्तमान हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए 13 प्रमुख सेक्टरों में सरकार से नीतिगत मदद की जरूरत रेखांकित की है।

इनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑटोमोटिव सुरक्षा व ड्रोन, टेक्सटाइल, सोलर पीवी, कैपिटल गुड्स, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, लेदर व फुटवियर, फार्मास्युटिकल्स, टेलीकाम उपकरण और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत की नई वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत तीन महत्वपूर्ण बातें उभरकर दिखाई दे रही हैं। एक, लम्बे समय तक व्यापार वार्ता चलाने के बजाय व्यापार वार्ता शीघ्रतापूर्वक पूरी की जाए। दो, व्यापार वार्ता के तहत मुख्य कारोबारी मुद्दों जैसे शुल्क, गैर शुल्क बाधाओं पर शुरुआत में ही प्राथमिकता के साथ विचार मंथन किया जाए। तीन, व्यापार वार्ता में भारत के लिए सिरमौर बने हुए सेवा निर्यात (सर्विस एक्सपोर्ट) को विशेष रूप से शामिल कराने पर ध्यान दिया जाए। पिछले दिनों 16 मार्च से 20 मार्च तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान लक्सन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, कृषि, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। खास बात यह कि पिछले 10 वर्षों से प्रस्तावित और धीरे-धीरे आगे बढ़ रही भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता वार्ता को अब शीघ्रतापूर्वक महज 60 दिन में पूर्ण करना भी सुनिश्चित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग (ईयू) की प्रेसिडेंट उर्सला वोन लेयेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु-परंतु को समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बारे में प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत-ईयू व्यापार समझौते पर इस वर्ष 2025 के अंत तक मुहर लगाई जाए। इसी तरह 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। फरवरी में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के व्यवसाय व कारोबार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक समझौते का उद्देश्य पांच से छह वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को तीन गुना करना है। ऐसे में भारत ने

ईयू की तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार व निवेश समझौते को इसी साल 2025 में पूर्ण करने के मद्देनजर रणनीति तय की है। यह उल्लेखनीय है कि इस समय जब दुनिया में द्विपक्षीय व्यापार समझौते नए सिरे से दोबारा अहम हो गए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के तहत जून 2024 से आगे बढ़ी व्यापार वार्ताओं को तेजी से पूर्ण करने और व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम पलटकर देखें तो पाते हैं कि गत वर्ष 13 से 15 जून को इटली में विकसित देशों के संगठन जी-7 के शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश के रूप में भारत शामिल हुआ और इस मौके पर सम्मेलन में शामिल प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं भी हुई। विगत 9 जुलाई को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मास्को में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा के बाद भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 22 सितंबर को न्यूयार्क में भारत और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में कई व्यापार समझौतों के साथ कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का करार हुआ है। भारत और चीन के बीच पांच साल बाद अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों का नया अध्याय दिखाई दे रहा है। इसी तरह विगत 16 दिसंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अपने सबसे पहले राजकीय विदेशी दौरे पर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई दिल्ली में लाभदायक द्विपक्षीय वार्ता की। अब दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने तथा पिछले वर्ष दिसंबर में की गई व्यापार वार्ताओं को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी आगामी माह अप्रैल में श्रीलंका जाएंगे। इन सबके साथ-साथ जहां नॉर्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली के साथ भी शीघ्र ही व्यापार समझौते की बातचीत शुरू हो सकती है, वहीं अब भारत द्वारा ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि अमेरिका के टैरिफ लगाए जाने की योजना का भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। विभिन्न नई शोध अध्ययन रिपोर्टों में यह बताया गया है कि ट्रंप की टैरिफ योजना से भारत के कुल निर्यात में महज 3 से 3.5 फीसदी गिरावट आ सकती है। निर्यात की इस कमी को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों से अधिक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस समय भारत दुनिया में सबसे अधिक 6.5 से 7 फीसदी विकास दर और सर्विस एक्सपोर्ट की वैश्विक राजधानी का तमगा हासिल करते हुए मजबूत घरेलू बाजार और रिकार्ड खाद्यान्न उत्पाद की ताकत के मद्देनजर दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। उम्मीद करें कि अमेरिका के द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की नई चुनौती के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और नए मुक्त व्यापार समझौतों की वार्ता के दौरान शुरुआत से ही शुल्क, गैर शुल्क बाधाओं पर प्राथमिकता के साथ बातचीत करने और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की नई रणनीति के अच्छे परिणाम बहुत जल्द सामने आते जाएंगे और वैश्विक वैल्यू चेन में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई देगी। ऐसे में भारत टैरिफ चुनौतियों के बीच विभिन्न देशों में कारोबार की नई संभावनाओं को मुट्ठियों में लेते हुए वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देगा।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

डिजिटल युग

डॉ. ज्योत्सना शर्मा

साइबर क्राइम की रोकथाम है ज़रूरी

आज के डिजिटल युग में, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। औद्योगीकरण के युग में मानव समाज ने बड़ी सहजता से प्रौद्योगिकी को अंगीकृत किया है। हमारे पास अलग-अलग तकनीकें हैं, साधन हैं जो हमारे घरेलू और कामकाजी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, जैसे ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी, जीपीएस और लोकेशन सर्विस, अलग-अलग नेटवर्क, 4जी और 5जी क्लाउड सर्विस, स्मार्ट होम, साइबर सुरक्षा और आजकल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम मेधा। इन सभी तकनीकों ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही हम कुछ गंभीर मुद्दों का सामना भी कर रहे हैं जैसे कि तेजी से बढ़ते हुए साइबर अपराध।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के अनुसार, दुनियाभर में अनुमानित 4.1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए, इंटरनेट सुरक्षा संबंधी खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध को किसी भी गैरकानूनी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अपराध करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। साइबर बेईमानी, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, फ़िशिंग, फिरौती, बाल शोषण, डेबिट/क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, क्रिप्टो जैकिंग कुछ प्रचलित साइबर अपराध के प्रकार हैं। इन अपराधों का समाज और व्यक्ति पर विभिन्न तरीकों से गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से किसी भी प्रकार का साइबर अपराध किसी व्यक्ति, कंपनी और संगठन को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सूचनाओं में हेरफेर करके आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी हो रहा है जिससे उन्माद भड़क जाते हैं और आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। साइबर अटैक तनाव और मानसिक दबाव पैदा करते हैं, जो किसी को भी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। 'क्राइम इन इंडिया' एनसीआरबी (स्त्रोत) के द्वारा प्रकाशित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत 65893 मामले(सीआर) दर्ज किए गए।साइबर अपराधों के लिए धोखाधड़ी के तहत वर्ष 2020-2022 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार 17470 मामले (सीआर) दर्ज किए गए। I4C ने सक्रिय रूप से डिजिटल अरेस्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की पहचान करके उन्हें ब्लॉक किया। भारत सरकार द्वारा 28.02.2025 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 आईएमईआई को ब्लॉक कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता पर लिया और देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना करके एक पहल की। विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करके साइबर अपराधों से निपटने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध से लड़ा जा सके और साइबर अपराध के रुझान और पैटर्न की पहचान करना, ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतों को आसानी से दर्ज किया जा सके और साइबर अपराधों को रोकने के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। साइबर फोरेंसिक जांच, साइबर हाईजीन, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। हम प्रौद्योगिकी को नकार नहीं सकते; हमें इसके साथ चलना होगा। कई तकनीकी संसाधनों के साथ, अब डिजिटल डिवाइड नहीं है और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ हम विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता के कई उदाहरण देख रहे हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ई-कॉमर्स हो आदि। ई-उद्यमिता आर्थिक विकास को गति दे रही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैश्विक स्तर पर उत्पाद का विपणन और ब्रांडिंग करने के लिए डिजिटल कौशल का उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर हम खुद को डिजिटल रूप से जागरूक रखते हैं, तो हम किसी भी तरह के साइबर अपराध से बच सकते हैं।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शारीरिक-मानसिक शुद्धिकरण का उपाय है उपवास

संकलित

दर्शन

हिंदू धर्म का पवित्र चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि आत्मशुद्धि और साधना का अवसर है। इस दौरान उपवास, ध्यान और पूजा से मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित कर आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक चेतना के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी दुर्गा की साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करेंगे। उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे ध्यान और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। हाल ही में उपवास की चर्चा केवल नवरात्रि तक सीमित नहीं रही। उपवास एक अलग संदर्भ में भी चर्चा का विषय बना, जब प्रसिद्ध अमरीकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लेने से पहले 45 घंटे तक उपवास किया। घोर भौतिकवादी समाज से आने वाले फ्रीडमैन ने इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि यह उपवास उनके लिए पीएम मोदी के साथ संवाद का सम्मान करने और उच्चतर 'आध्यात्मिक स्तर' तक पहुंचने का एक उपाय था। यह घटना दर्शाती है कि उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। उपवास आध्यात्मिक उन्नति और आत्म-अनुशासन का भी एक सार्वभौमिक साधन है, जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। पश्चिमी वैज्ञानिक और दार्शनिक भी अब उपवास के लाभों को समझ रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में उपवास, जिसे लंघन के नाम से भी जाना जाता है, को बहुत महत्व दिया जाता है।

आपके भीतर की मनःस्थिति है खुशी का रहस्य

संकलित

प्रेरणा

दुनिया की सभी शिक्षाएं महान खुशी पाने की बात करती हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही वह चीज है, जिसे हर कोई आखिरकार खोज रहा है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है, यह बस एक मनःस्थिति है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं, यह पहले से ही आपके भीतर है, यहीं और अभी। हम जो कुछ भी बाहर चाहते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर है। जीवन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। इसे माया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई आपसे प्यार करता है, तो यह परेशानी हो सकती है और अगर वह आपसे प्यार नहीं करता, तो यह भी परेशानी है। दोस्त और दुश्मन दोनों ही परेशानी का कारण हो सकते हैं। इसलिए यह संकल्प लेना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुशी नहीं खोऊंगा। भले ही आपको व्यापार, रिश्तों या जीवन के किसी भी दूसरे पहलू में नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए। यह आपके विकास का एक पैमाना है। जब आप खुशी के स्रोत पर जाते हैं, तो आपकी इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, आपका मन संतुष्ट हो जाता है और चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। परफेक्ट होने के बारे में तनाव न लें। अगर आप परफेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप गुस्सा महसूस करेंगे। दुनिया अपूर्ण लग सकती है, लेकिन अंदर से सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्शन छिपा हुआ है, जबकि अपूर्णता दिखाई देती है।

ट्रेंड

सहकारी शिक्षा

अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएँगे।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

भाषा विवाद गलत

जो लोग संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते यह भाषा विवाद खड़ा कर रहे है, उनका राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन, वो रोजगार पर प्रहार कर रहे हैं। इसीलिए वो राज्य पिछड़ते जा रहे हैं।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

विपक्षी दल एकजुट

सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार के असंवैधानिक और विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए संसद में मिलकर काम करेंगे।

- मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

नंदघर का सपना

जब नंदघर का सपना देखा था, सिर्फ एक ही सोच थी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और पोषण मिले, हर महिला के हाथ में रोज़गार हो। आज, 15 राज्यों में 8000 से अधिक नंदघरों के साथ, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य संवर रहा है और 2.5 लाख महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी हैं।

-अनिल अग्रवाल, उद्यमी

नगर परिषद वार्डों के परिसीमांकन के संबंध में 17 अप्रेल तक आपत्तियां आमंत्रित

राजस्थान की राजनीति

दौसा (विष्णु आशीर्वाद)। नगर परिषद दौसा के प्रस्तावित वार्डों के संबंध में प्रारूप प्रकाशन होने के बाद 17 अप्रेल तक जनसाधारण की आपत्तियां आमंत्रित की गई है। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि स्वायत शासन विभाग ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों के गठन एवं परिसीमांकन के निर्देश दिए थे। इसके पश्चात् जिले की नगर परिषद दौसा में क्षेत्र विस्तार के बाद कुल वार्ड 55 निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के प्रस्तावित वार्डों के संबंध में संलग्न प्रपत्र क एवं ख में प्रारूप प्रकाशन होने से 21 दिवस की अवधि में अर्थात 17 अप्रेल की सायं 6 बजे तक जनसाधारण की आपत्तियां आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति वार्डों के संबंध में लिखित आपत्ति नगर परिषद आयुक्त कार्यालय, दौसा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय तथा जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

राकेश कुमार मीणा को अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की मिली उपाधि

राजस्थान की राजनीति

नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग में कार्यरत राकेश कुमार मीणा (गाँव-मोहनपुर, किसान धर्म सिंह मीणा के पुत्र) को द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, यूएसए (तक्कर), द्वारा डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नोएडा में आयोजित पीस कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी में डॉ. मार्क बर्न्स (यूएसए राष्ट्रपति मा0 डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार) डॉ यासीनिया (जैसी) सांचेज़, रिप्रेजेंटेटिव ऋव्र, यूएस प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड नेशन्स, प्रो. डॉ. मधु कृष्ण, चेयरमैन कम चीफ रेक्टर, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, अमेरिका, डॉ. नीरज टंडन, डीन एंड डायरेक्ट, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, अमेरिका (इंडिया चैप्टर) एवं प्रो. डॉ. पूनम टंडन, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश?वविद्यालय, तथा देश विदेश से आए एंबेसडर्स, साइंटिस्ट्स, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स आदि मौजूद रहे। द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, यूएसए (तक्कर), पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति के लिए कार्यरत है। पीस कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी में भारत के कुल 15 सदस्यों को उपाधि प्रदान की गई, जिसमें तीन उपाधि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को प्रदान की गई। डॉ राकेश कुमार मीणा, डॉ नौरतन सिंह और डॉ आदित्य शिवहरे ने ह्यूमैनिटी के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, इसीलिए उन्हें ये उपाधि और सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, यूएसए द्वारा दिए गए। डॉ राकेश कुमार मीणा की यह उपलब्धि उनके परिवार, गाँव और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के लिए गौरव का विषय है।

मंदिर जा रहे डॉक्टर को सीबीएन ने पकड़ा

पूर्व विधायक और लोगों ने षड़यंत्र के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया, दोपहर बाद छोड़ा

राजस्थान की राजनीति

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एनसीबी टीम ने बुधवार सुबह मंदसौर के डॉक्टर डीडी संगतानी को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर अपने परिवार के साथ नालछा माता मंदिर जा रहे थे। टीम परिवार की महिलाओं को उतारकर डॉक्टर को प्रतापगढ़ ले आई।

डॉक्टर के खिलाफ षड़यंत्र किया गया-पूर्व विधायक

मंदसौर के पूर्व विधायक सिसौदिया ने कार्रवाई को पूरी तरह फर्जी बताया। साथ ही बिना वारंट या स्पष्ट कारण की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा-अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी के अंदर से एमडी बरामद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एमडी उस व्यक्ति ने रखी है जो लगातार इस परिवार को परेशान कर रहा है। सात-सात झूठे प्रकरण बनवाए। प्रशासन भी जानता है कि इन सबके पीछे कौन है। विभाग ने तो अपना काम किया, लेकिन पत्नी के साथ नवरात्रि में मंदिर जा रहा व्यक्ति कभी गाड़ी में एमडी नहीं लाएगा। इन्हें षडयंत्र का शिकार बनाया गया है।

डॉक्टर का चल रहा पारिवारिक विवाद

वहीं सिंधी समाज प्रवक्ता अनिल लालवानी ने बताया-डॉक्टर संगतानी को एमडी ड्रग के मामले में संदिग्ध आरोपी बनाकर केस बनाया या नहीं लेकिन गिरफ्तार कर नारकोटिक्स टीम प्रतापगढ़ लेकर आई है। डॉक्टर संगतानी का पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा है। पहले भी उनके खिलाफ किए गए मामले फर्जी साबित हो चुके है। डॉक्टर के खिलाफ फर्जी मुकदमा बनाया गया है, इसलिए हम लोग यहां आए है।

परिवार ने अपहरण की शिकायत दी

इधर परिवार ने इसे अपहरण बताते हुए स्थानीय समाज और जनप्रतिनिधियों को सूचित किया। करीब 200 लोग एनसीबी कार्यालय पहुंचे। दोपहर बाद एनसीबी की टीम ने डॉक्टर को छोड़ दिया। इधर सीबीएन के प्रतापगढ़ अधीक्षक बीएन मीणा ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

वक्फ बिल का विरोध

मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शनः जयपुर में एसडीपीआई का प्रदर्शन, संगठनों ने बताया संविधान विरोधी

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया।

राजधानी जयपुर के एमडी रोड पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि यह संशोधन लोकतंत्र के विरुद्ध है। उनकी मांग है कि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश न किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा।

जमाते इस्लामी हिंद के केंद्रीय सहायक सचिव डॉ. इकबाल अहमद ने बिल को मुस्लिम समाज के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियां हड़पना चाहती है। इसलिए बिल को जल्दबाजी में लाया गया है।

मुस्लिम संगठनों की मांग है कि अगर वक्फ में संशोधन करना है, तो देवस्थान विभाग सहित अन्य धार्मिक बोर्डों में भी संशोधन किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सभी मुस्लिम संगठन एकजुट होकर बिल का विरोध कर रहे हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि बिल लागू होने पर आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

राजस्थान में 19 हजार वक्फ संपत्ति

राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानु खान बुधवाली का कहना है कि राजस्थान में 19 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, उन्होंने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बिल में संशोधन कर रही है वो सही नहीं है, सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म करना चाहती है, कलक्टर को पावर देकर गलत कर रही है, इससे वक्फ संपत्तियां खुर्द होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि सरकार भ्रम फैला रही है कि वक्फ एक्ट में महिलाओं को नहीं लिया जाता है जबकि पहले से ही वक्फ बोर्ड में दो महिला सदस्य नियुक्त किया जा रहे हैं. केंद्र सरकार केवल वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है इसलिए ये बिल लाया जा रहा है.

धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप

राजस्थान हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा कि मुस्लिम कौम के धार्मिक मामलों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिस प्रकार से अन्य धार्मिक बोर्ड है, उसमें अन्य धर्म के व्यक्ति को किसी भी पोस्ट पर नहीं लिया जाता इसी तरह से वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम व्यक्ति को ही लिया जाता है, वक्त की जो संपत्ति होती है वह लोगों के द्वारा दान की जाती है ताकि वह मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार के लिए काम आ सके लेकिन केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है.

वक्फ संपत्तियों पर सरकार की गलत नज़र

युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि किसी धर्म की जमीन पर मालिकाना हक उसकी संस्था का ही होता है। उसके साथ छेड़खानी करना किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से संपत्तियों को भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश भर में अराजकता फैला रहे हैं नफरत हिंसा फैला रहे हैं।

संजू सैमसन फिर संभालेंगे राजस्थान रॉयल्स की कमान

किंग्स इलेवन पंजाब के सामने बतौर विकेटकीपर और कप्तान उतरेंगे मैदान में

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी अब एक बार फिर संजू सैमसंग करते हुए नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस ने बुधवार को संजू सैमसन को विकेट कीपिंग और टीम की कमान संभालने की अनुमति दे दी है। इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब के साथ होने वाले मुकाबले में संजू सैमसन बतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बनेंगे।

दरअसल, 12 दिन पहले 20 मार्च को आईपीएल शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बड़ा बदलाव किया था। टीम की कमान संभालने वाले संजू सैमसन की जगह ऑलराउंडर रियान पराग को कप्तानी की कमान सौंपी गई थी। लेकिन, अब फिर से संजू सैमसन इस कमान को संभालेंगे।

हाथ में चोट लगने की वजह से नहीं मिली थी परमिशन

पिछले दिनों टीम इंडिया के साथ खेलते हुए संजू सैमसन के हाथ में चोट लग गई थी। इसके बाद से ही उन्होंने BCCI के नेशनल एक्सीलेंस सेंटर द्वारा विकेट कीपिंग और कैप्टेन्सी की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन में रियान पराग को शुरुआती 3 मैच के लिए टीम का कप्तान बनाया था। वहीं चेन्नई के साथ हुए मुकाबले के बाद संजोग एक बार फिर फिटनेस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। जहां उन्होंने नेशनल एक्सीलेंस सेंटर में मंगलवार को अपना फिटनेस टेस्ट दिया था। इसके बाद बुधवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में संजू सैमसन अब फुल टाइम प्लेयर के तौर पर विकेट कीपिंग और कैप्टेन्सी के साथ राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले संजू सैमसन को इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बतौर बल्लेबाज खेलने की अनुमति मिली थी। वो उंगली की चोट के कारण ना तो फील्डिंग कर सकते थे और ना ही विकेटकीपिंग। ऐसे में चेन्नई से हुए मैच के बाद खुद को फिट महसूस होने पर संजू ने खुद का फिटनेस टेस्ट करने का फैसला किया था।

हरियाणा की लेडी सरपंच के क्रश सचिन पायलट

वीडियो वायरल हुआ तो बोलीं-गलत मतलब निकाला; खट्टर के पैर में दुपट्टा फेंक चुकीं

राजस्थान की राजनीति

सिरसा। हरियाणा की लेडी सरपंच नैना झोरड़ के क्रश राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। नैना का कहना है कि वह कभी सचिन पायलट से मिली तो नहीं, लेकिन 14 साल की उम्र से उन्हें पसंद करती थीं। वह सौम्य, सहज, सुंदर और शांत हैं। मुझे कभी सचिन पायलट से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मिलूंगी जरूर। नैना का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

हालांकि बाद में नैना ने इस पर सफाई दी कि पर्सनैलिटी के तौर पर सचिन अच्छे लगते हैं, लोग इसे गलत तरीके से ले रहे हैं कि सचिन का तलाक हो गया तो उनसे शादी कर लो। ऐसे तो कोई सलमान खान को पसंद करे तो क्या उससे शादी कर ले। लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए। नैना इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) से जुड़ी हुई हैं। उन्हें सिरसा की महिला विंग का प्रधान बनाया गया है। नैना तब सुर्खियों में आई थी, जब एक जनसभा के दौरान उन्होंने तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के पैरों में अपना दुपट्टा फेंक दिया था। हालांकि नैना ने मौजूदा ष्टरू नायब सैनी की खुलकर तारीफ भी की।

पाकिस्तान दुश्मन नहीं, सीएम सैनी अच्छे नेता

नैना झोरड़ ने कहा कि मुझे घूमने का शौक है। मैं एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हूं। पाकिस्तान की आम अवाम भी हमारे जैसी है। मैं पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानती। वह भी बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। वहीं भाजपा के विरोध पर नैना ने कहा कि मैं किसी दल के खिलाफ नहीं हूं। पूर्व सीएम मनोहर लाल का व्यवहार ठीक नहीं लगा तो इनेलो को समर्थन दे दिया। अब इनेलो के साथ हूं। बार-बार दल बदलना ठीक नहीं है। सीएम सैनी अच्छे राजनेता हैं।

खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम में गईं थी नैना

नैना ने मई 2023 में सिरसा में मनोहर लाल खट्टर के पैरों में दुपट्टा फेंका था। यहां मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे। तब बणी गांव की सरपंच नैना झोरड़ शिकायत लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरे पति पर झूठा केस दर्ज किया गया है। जिसके बाद वहां पर कुछ बहस हुई और नैना ने अचानक अपना दुपट्टा निकालकर खट्टर के पैरों में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया। वहीं खट्टर ने भी जांच के आदेश दे दिए। नैना का कहना था कि पति पर ही हमला हुआ और उन्हीं पर केस दर्ज कर लिया गया।

सचिन पायलट टोंक से ऋरू, उनका तलाक हो चुका

सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इस वक्त वह टोंक विधानसभा से कांग्रेस के MLA हैं। उनकी शादी जम्मू कश्मीर के मौजूदा CM उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से जनवरी 2004 में हुई थी। सचिन अमेरिका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हॉर्टन स्कूल में थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात सारा से हुई। जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। पहले अब्दुल्ला परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मगर, सचिन पायलट 26 साल की उम्र में दौसा से सबसे युवा सांसद बने तो उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि पिछले साल टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ने के एफिडेविट में सचिन ने खुद को तलाकशुदा बताया तो उनके सारा से तलाक होने का खुलासा हुआ था।

राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार

हाई कोर्ट ने नियुक्ति नहीं करने पर स्वप्रेरणा से दर्ज मामले को किया निस्तारित

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर एकलपीठ द्वारा स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका को खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया। आज मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करना सरकार का विशेषाधिकार हैं। दरअसल, 16 मार्च को एकलपीठ ने हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की सहमति के बाद भी अधिवक्ता ब्रह्मानंद सांदू की राजकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त को लेकर निर्णय नहीं लेने पर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वप्रेरणा से याचिका दायर की थी। वहीं स्पष्टीकरण देने के लिए प्रमुख शासन सचिव विधि को तलब किया था।

यह जनहित से जुड़ा मामला नहीं

अदालत ने आदेश में कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है और ऐसे में इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है।

अदालत ने अधिवक्ता सांदू को छूट दी है कि वे चाहे तो इस संबंध में अलग से सर्विस रिट पेश कर सकते हैं। अधिवक्ता सांदू ने कहा कि मार्च 2024 में उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और तब उन्हें पता चला था कि राज्य सरकार ने उनका नाम जयपुर पीठ में जीए-एएजी पद के लिए तय किया है।

वहीं हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से भी माना कि उनके नाम की सहमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित हैं। इस पर अदालत ने प्रकरण को निस्तारित कर दिया।

डोटासरा बोले- लक्ष्मणगढ़ में सरकारी लोकार्पणों में मुझे नहीं बुलाया

कहा- पर्ची को सत्यानाश कहने वाले किरोड़ी पर्ची बदलवाने में लगे, राइजिंग राजस्थान में फर्जी एमओयू हुए

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर विपक्षी विधायकों को सरकारी लोकार्पण, उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि इस सरकार ने नई परंपरा निकाल दी है, हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। अभी सीएम ने उद्घाटन किए, एक भी कांग्रेस के विधायक को लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में भी लोकार्पण कार्यक्रम हुए लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया गया। डोटासरा ने कहा- मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूं, मेरे वक्त में कॉलेज मंजूर हुआ था, मुख्यमंत्री ने कब उद्घाटन किया किसी को पता नहीं। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मुझे बताया, मेरी नाम पट्टिका जरूर लगी थी।

डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

किरोड़ी ने कहा था पर्ची ने सत्यानाश कर दिया, अब वो पर्ची बदलवाने में लगे हैं

डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसते हुए कहा- किरोड़ी ने कहा था कि पर्ची ने मेरा सत्यानाश कर दिया मुझे चुनाव हरवा दिया, अब वो पर्ची बदलवाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि पर्ची बदलती है या पर्चा बदलता है, या फिर पोर्टफोलियो बदलता है। नौ महीने से मंत्री खुद मान रहे थे कि वे काम नहीं कर रहे हैं। इस सरकार की हाल देखिए, डबल इंजन की सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, यह जनता का विषय नहीं है, जनता ने भाजपा की सरकार चुनी है तो उसे काम करना चाहिए।

बड़े उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए हुआ राइजिंग राजस्थान का नाटक

डोटासरा ने राइजिंग राजस्थान को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा-

मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निवेशक उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। जब फर्जी एमओयू करवाओगे तो यही हाल होगा। राइजिंग राजस्थान में बड़ा खेल हुआ है, जिनकी पर्ची दिल्ली से आई है उन्हें सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन दे दी। कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो केवल जमीन देने का काम होता है। सोलर के लिए जमीन देने से कोई रोजगार नहीं मिलता।

बड़े उद्योगपतियों को सोलर के लिए जमीन देने में कई भाजपा के नेता भी शामिल हैं। राइजिंग राजस्थान का नाटक केवल बड़े उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए किया गया था, हम इसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे।

सरकार अपने चहेतों को वक्फ संपत्तियों का मालिक बनाना चाहती है

वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर डोटासरा ने कहा- वक्फ संपत्तियों पर सरकार की नीयत में खोट है। केंद्र सरकार अपने चहेतों को वक्फ संपत्तियों का मालिक बनाना चाहती है, इसीलिए मनमाने तरीके से बिल लेकर आ गए हैं। इसके जरिए हिंदू- मुसलमान ध्रुवीकरण भी हो जाएगा और राजनीतिक रोटियां भी सेक ली जाएंगी।

डोटासरा ने कहा- वक्फ संपत्तियों पर पहले से ही कानून बना हुआ है, जिसमें वक्फ संपत्तियां सुरक्षित हैं। अब ये लोग वक्फ एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं, इनसे पूछा जाए कि वक्फ एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी इनसे कारण पूछे तो ये जवाब देने की जगह भ्रम फैलाने लग जाते हैं कि नई संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। इनसे पूछा जाए कि जो पहले से संसद भवन बना हुआ है क्या उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया था

Tni आवाज़

उत्तरप्रदेश की राजनीति

E-mail: tniawaz.news@gmail.com
www.hpnews.in/www.tniwaaaz.in

आपकी आवाज के साथ....

www.uttarpradeshkirajneeti.com

जयपुर, गुरूवार 03 अप्रैल, 2025

HP NEWS हिन्दुस्तान की आवाज़
हिन्दुस्तान पत्रिका
HINDUSTAN KI AWAZ

आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, मथुरा,अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज,बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर,औरैया, इटावा, फ़र्रूख़ाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर से प्रसारित

इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन दिवस केक काटकर मनाया

उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा। मथुरा में 108-102 एंबुलेंस कर्मचारियों ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन दिवस बड़े उत्साह के साथ बुधवार को सीएमओं कार्यालय में मनाया। कार्यक्रम में सीएमओ डा. ए के वर्मा, डा. भूदेव सिंह वाहन प्रभारी के साथ मिलकर केक काटकर शपथ लेते हुए सीएमओ और वाहन प्रभारी ने अच्छा कार्य करने वाले सात ईएमटी प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले भंवर सिंह, ओमवीर सिंह, अनुज कुमार, हरीश कुमार, कुलदीप कुमार, ह्रदेश कुमार, अवनीश कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधिकारी डा.आलोक कुमार,डा.रोहिताश,डीपीएम संजय सिहोरिया,एंबुलेंस प्रोग्राम मैनेजर गौरव त्यागी आदि मौजूद थे।

शिक्षा भविष्य संवारने की रखती है शक्ति- आरिफ मोहम्मद खान

बिहार के राज्यपाल ने लोहवन के स्कूल में व्यक्त किए विचार

उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहवन के नवीनीकृत निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इन दोनों विद्यालयों का सनश्योर एनर्जी द्वारा सीएसआर के फंड से दो विद्यालयों का नवीनीकृत कार्य कराया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज की प्रगति सुनिश्चित हुई है। शिक्षा न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, बल्कि हमारे संयंत्रों के आस-पास के समुदायों के समग्र विकास को भी उत्प्रेरित करती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली मार्ग है जिसके माध्यम से हम एक मजबूत, अधिक विकसित भारत के निर्माण में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ÷शिक्षा ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमारे भविष्य को संवारने की शक्ति रखता है। स्कूल में हर कदम एक मजबूत, उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। स्वच्छ ऊर्जा इस दिशा में एक गहरी प्रेरणा है और युवा लड़कियों को सही समय पर सशक्त बनाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है।

सुबह-सुबह थाने पहुंच गई दुल्हन, बोली - शादी का सुख तो मिला लेकिन....

उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा। मथुरा में इंटरनेट मीडिया में वर्दी के साथ फोटो और रील डालकर महिलाओं को शादी का झांसा देकर फंसाने वाले फर्जी असिस्टेंट कमांडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूछताछ में उसने अर्द्धसैनिक बल, आरपीएफ आदि में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने की 21 वारदात स्वीकार की हैं. आरोपी प्रयागराज का रहने वाला है.

मथुरा में एक युवती के भाई को नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे शादी की थी. वह खुद को असिस्टेंट कमांडेंट बताता था. उसके कब्जे से पुलिस का स्टीकर लगी एक लग्जरी कार, एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट का आइकार्ड, सीआरपीएफ यूनिफार्म ,बेल्ट, नेम प्लेट बोर्ड, यूपी पुलिस की कैप, दो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नौ एटीएम कार्ड, एक दर्जन व्यक्तियों के आधार कार्ड, दो लैपटॉप, लैपटॉप में बड़ी संख्या में फौज के जवान, अधिकारियों के फोटो बरामद की गई है. हाईवे थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही ने बताया कि आरोपी प्रयागराज में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का काम करता था. बीमा कराने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के कई कैंप में विजिट करता था. वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाकर सीआरपीएफ की वर्दी में फोटो-रील बनाकर फर्जी असिस्टेंट कमांडेंट बनकर लोगों से ठगी करता था. अद्धसैनिक बल, आरपीएफ और अन्य विभाग में सरकारी नौकरी लगाने का लालच देता था. कई महिलाओं को भी झांसा देकर उनसे शादी करने का लालच दिया. आरोपी शादीशुदा है. दो बेटियां हैं. खुद को कुंआरा बताकर पीड़िता से शादी करने का झांसा दिया था. आरोपी की पहचान प्रयागराज के लौवा कौन थाना कुरौव निवासी हरीश कुमार उर्फ सौरभ श्रीवास्तव के रूप में हुई. मुकदमा हाईवे थाने में भी दर्ज हुआ था.

अखिलेश बोले- इतनी बड़ी भाजपा, अध्यक्ष नहीं चुन पा रही

शाह का जवाब- आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं; हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा

उत्तरप्रदेश की राजनीति

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कसा।

अखिलेश ने कहा- भाजपा में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा है। जो पार्टी यह कहती हो कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह यह नहीं तय कर पा रही कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।

इस पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से उठे और हंसते हुए कहा- सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 लोगों को चुनना है, परिवार को। हमारे यहां करोड़ों लोग हैं। समय तो लगेगा ही।

अखिलेश जी ने यह बात हंसते हुए कही, इस वजह से मैं भी हंसते हुए कह रहा हूं। आपके (अखिलेश के) यहां जरा भी देर

नहीं लगेगी। मैं कहता हूं आप 25 साल तक अध्यक्ष हो.. जाओ..।

इसके बाद अखिलेश ने हंसते हुए फिर कहा- अभी जो यात्रा हुई है नागपुर की और गुपचुप जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वह 75 साल के एक्सटेंशन की यात्रा तो नहीं है।

बिरला बोले- अखिलेश जी, वक्फ के मुद्दे पर भी आ जाओ

प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए थे। अखिलेश का इशारा इसी दौरे को लेकर था।

संसद में अखिलेश यादव अपनी बात रखते कभी महाकुंभ तो कभी नोटबंदी पर बोलने लगे। इसके बाद महंगाई, गंगा सफाई और किसानों की समस्याएं बताने लगे। उन्हें इन मुद्दों पर बोलते-बोलते 5 मिनट हो गया, तभी स्पीकर ओम बिरला को टोकना पड़ा। कहा- 'अखिलेश जी, वक्फ के मुद्दे पर भी आ जाओ।'

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन बोले- पिछलग्गू पार्टी के नेता का बयान वायरल

JDU सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा- ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है।

उन्होंने कहा- कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी के नेता का बयान वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा था- पटना का चौराहा पूरा वक्फ ने कब्जा कर रखा है, कड़ा कानून बनना चाहिए। किरण रिजिजू का धन्यवाद कि देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट को वक्फ की संपत्ति बनने से बचा लिया।

भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने

भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने मिले की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मार्च को मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की।

वक्फ बोर्ड का फायदा सिर्फ बड़े लोग उठा रहे, संशोधित बिल पर बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

उत्तरप्रदेश की राजनीति

मथुरा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज मथुरा के महावन में एक सरकारी स्कूल के नवीनीकरण के बाद उसका उद्घाटन किया. इस अवसर पर, आयोजकों ने राज्यपाल खान का स्मृति चिन्ह और दुपट्टा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक पूरन प्रकाश भी उपस्थित थे. मीडिया से बातचीत करते हुए, राज्यपाल खान ने वक्फ बोर्ड संशोधित बिल पर अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जब वे वक्फ बोर्ड के मंत्री थे, तब से उन्होंने देखा है कि वक्फ बोर्ड की अधिकांश संपत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें वर्षों पहले एक व्यक्ति ने मालिक बना लिया था. अब, उन संपत्तियों का उपयोग गरीबों या धर्म के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके अनुभव के अनुसार, इन संपत्तियों में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में 90 प्रतिशत वक्फ भूमि पर मुकदमे चल रहे हैं और उनका उपयोग

गरीबों के लिए कॉलेज, अस्पताल या धार्मिक कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा है. राज्यपाल खान ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश में मंत्री थे और वक्फ विभाग उनके पास था, तो 90 प्रतिशत से अधिक मुकदमे थे. उन्होंने लोगों से अपने जिलों में वक्फ की स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया और पूछा कि क्या उनके पास कोई धर्मार्थ कार्य हो रहा है, जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनाथालय. उन्होंने कहा कि वर्तमान में, इन संपत्तियों का लाभ केवल बड़े लोग उठा रहे हैं, और इसमें सुधार की आवश्यकता है. वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है. भारत में, वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित होते हैं. राज्यपाल खान का अनुभव और टिप्पणी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।

आगरा यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के खिलाफ कोर्ट में याचिका

वकील बोले- मैं रजिस्ट्रार से मिलने गया था, अभद्रता करते हुए मुझे टोपादास कहा

उत्तरप्रदेश की राजनीति

आगरा। आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर एक वकील ने आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जब वह कुलसचिव से विश्वविद्यालय में मिलने गया था तो कुलसचिव ने उनसे कहा था- टोपादास तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक आईएएस अधिकारी के सामने बोलने की।

अधिवक्ता ने कुलसचिव पर मानहानि के साथ लोक सेवक के रूप में सही तरीके से कार्य नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई को याचिका डाली है।

कृष्ण गोपाल हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने आगरा कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां एक याचिका डाली है। इसमें उन्होंने कहा है कि तीन फरवरी 2025 को शाम करीब 4ः30 बजे वह कुलसचिव के कार्यालय में लोकमणि शर्मा महाविद्यालय के द्वारा कूटरचित तरीके से मान्यता लेने के संबंध में हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है।

यह जानकारी करने आए थे। कृष्ण गोपाल का कहना है कि उनकी मां का देहांत हो गया था, मुंडन की वजह से उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। जब वह कुलसचिव राजेश कुमार यादव से मिलने पहुंचे, तो वकील ने आरोप लगाए हैं कि रजिस्ट्रार ने कहा कि टोपादास तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक आईएएस अधिकारी के सामने बोलने की। बाहर निकल जाओ नहीं तो धक्के मरवाकर निकलवाना पड़ेगा।

यह सुनकर वह डर गए और बाहर निकल आए। वकील कृष्ण गोपाल का कहना है राजेश कुमार द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे उन्हें काफी मानसिक पीड़ा हुई है। राजेश कुमार के द्वारा जानबूझकर उनके अनुस्मारक पत्र को वापस कर विधि द्वारा दिए गए।

निर्देशों को अनदेखा कर उनकी अवहेलना की गई है। न्यायालय में उन्हें दंडित करने की गुहार लगाई गई है। इस याचिका पर 29 अप्रैल सुनवाई की डेट कोर्ट ने दी है।

ट्रेन में करने वाले थे चोरी, जीआरपी ने दबोचा: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर दो चोर गिरफ्तार, 3 लाख की ज्वैलरी बरामद

उत्तरप्रदेश की राजनीति

आगरा। आगरा में थाना जीआरपी कैंट द्वारा दो चोरों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ट्रेन में चोरी की योजना बना रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से तीन लाख रुपये की ज्वैलरी बरामद हुई है।

ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और चोरों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में चेकिंग की जाती है। थाना जीआरपी आगरा कैंट के नेतृत्व में गठित जीआरपी टीम ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से

ग्वालियर के दो चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चोरी किये गये तीन लाख रूपये की ज्वैलरी बरामद हुई है। एक का नाम बॉबी कुशवाह और दूसरे का नितिन परिहार है। इनके साथी अनिकेत की तलाश है। तीनों योजना बनाकर ट्रेनों में चढ़ते थे। रात में जब सो जाते थे, तब यह लोग गले से चेन, उंगलियों से अंगूठी, चेन, चूड़ियां आदि उतार लेते थे। कई बार यह लोग स्टेशन पर ट्रेन के चलने पर गले से चेन या मंगलसूत्र खींच कर भी भाग जाते थे। तीनों पर दो मुकदमे भी दर्ज थे। इनके पास से चेन, हार, अंगूठी बरामद हुई है। जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। बॉबी और नितिन पर ग्वालियर में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।

नगर निगम ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना: निरीक्षण पर निकले नगर आयुक्त को मिली थी कार्य में लापरवाही, गंदगी पर भी जताई नाराजगी

उत्तरप्रदेश की राजनीति

आगरा। सड़क पटरी के निर्माण में लापरवाही बरतने पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वे बुधवार सुबह शहर के निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान ठेकेदार की लापरवाह उजागर हुई।

नगर आयुक्त ने बुधवार सुबह कारगिल पेट्रोल पंप, ईंट मंडी, बोदला रोड होते हुए शास्त्रीपुरम और पश्चिमपुरी का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को परखा। कारगिल पेट्रोल पंप से ईंट की मंडी तक सड़क के दोनों तरफ गंदगी पाये जाने पर उसे साफ कराने और वहां लगी ठेल धकेल को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वहीं भारत मार्बल कंपनी के संचालक द्वारा सड़क किनारे टूटी टाइल्स आदि

डालने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उस पर जुर्माना लगाने के लिए कहा।

ग्रीन नेट तक नहीं लगाया था

ईंट की मंडी क्षेत्र में सड़क पटरी का निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाये जाने, निर्माण कार्य को ग्रीन नेट से कवर न करने और बालू पर पानी का छिड़काव न करने आदि के साथ एनजीटी की गाइड लाइंस का पालन न करने पर उन्होंने मुख्य अभियंता को ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। इसके द्वारा जो फुटपाथ बनाया जा रहा है, वह भी मानकों के अनुरुप नहीं था।

जमीन की बाउंड्री कराने के आदेश

पश्चिमपुरी चौराहे पर उन्होंने होर्टिकल्चर गार्डन विकसित करने के लिए सहायक लेखधिकारी विपिन यादव को निर्देशित किया। प्राची टॉवर के निकट नगर निगम की खाली पड़ी भूमि की बाउंड्रीवाल बनाने के साथ ही इसमें लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाने के आदेश भी उन्होंने मुख्य अभियंता को दिये।

तेज हवाओं के साथ आज हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने किया अलर्ट, लगातार 3 दिन से तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी

उत्तरप्रदेश की राजनीति

आगरा। आगरा का मौसम एक बार फिर पलट सकता है। गुरुवार को बदलाव के संकेत हैं। बादल छाए रहने के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कहीं बौंछार भी पड़ सकती ह। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।

वहीं, आगरा में लगातार 3 दिन से तापमान में बढ़ोत्तरी जारी है। 2 अप्रैल को अधिकत तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 1 अप्रैल की तुलना में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी रही।

344 विद्यार्थियों को डिग्री और 21 को मिलेंगे गोल्ड मेडल

रैफल्स यूनिवर्सिटी का छठा दीक्षांत समारोह 5 अप्रैल को होगा आयोजित, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। नीमराणा स्थित रैफल्स यूनिवर्सिटी अपना छठा दीक्षांत समारोह 5 अप्रैल, शनिवार को यूनिवर्सिटी कैम्पस में आयोजित करने जा रहा है।

समारोह का आयोजन सुबह 10.30 बजे से होगा, जिसमें भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, जस्टिस दीपांकर दत्ता और एमार, दुबई के संस्थापक मोहम्मद अलब्बर, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

रैफल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो. (डॉ.) राजेंद्र सिंह सांगवान ने बताया कि समारोह का एक प्रमुख आकर्षण मोहम्मद अलब्बर को डॉक्टरेट डिग्री (ऑनोरिस कॉसा) से सम्मानित करना भी होगा। दीक्षांत समारोह की शुरुआत अकादमिक प्रोसेशन के साथ होगी। इस दौरान कुल 344 विद्यार्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। यह डिग्रियां उन्हें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लॉ, ह्यूमैनिटीज, फार्मेसी,और बेसिक एंड एप्लाइड साइंस आदि सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के 21 गोल्ड मेडलिस्ट्स को मेडल्स देकर सम्मानित किया जाएगा।

समारोह की अध्यक्षता, यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन विवेक गोम्बेर करेंगे। इस अवसर पर गोम्बेर एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरपर्सन, डॉ. जस्टिस मीना वी. गोम्बेर भी उपस्थित रहेंगे। समारोह की शुरुआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) राजेंद्र सिंह सांगवान द्वारा वेलकम एड्रेस के साथ होगी। जिसके बाद वे यूनिवर्सिटी की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। समारोह का समापन रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) के. कार्तिकेयन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ होगा।

जयपुर डेयरी लॉन्च करेगी 23 नए प्रोडक्ट

5 रुपए में मिलेगी आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, कोल्ड कॉफी और श्रीखंड के अलग-अलग फ्लेवर मिलेंगे

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लि. (जयपुर डेयरी) इस गर्मी सीजन में 23 नए प्रोडेक्ट आमजन के लिए लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी के अलावा श्रीखंड के नए फ्लेवर्ड प्रोडक्ट है।

दरअसल, 5 अप्रैल को जयपुर डेयरी में कार्यक्रम होगा, जिसमें इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इन प्रोडक्ट में सरस की ओर से 5 रुपए की आइसक्रीम भी होगी। वहीं श्रीखंड के भी अलग-अलग फ्लेवर होंगे।

चेयरमैन बोले-आमजन की मांग को देखते हुए लिया फैसला

जयपुर डेयरी के चेयरमेन ओम पूनिया ने बताया- बाजार में आमजन की मांग को देखते हुए हमने ये फैसला किया है। वर्तमान में दूसरी डेयरी कंपनियां अपने प्रोडेक्ट बाजार में बेच रही है और आमजन की डिमांड सरस को लेकर ज्यादा है। क्योंकि सरस के दुग्ध उत्पादों की शुद्धता और विश्वसनीयता आज भी बाजार में सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए हमने आईसक्रीम, श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी बाजार में लॉन्च करने का निर्णय किया है। ये सब उत्पाद हमारे यहां प्लांट में ही बनाए जा रहे है। इसमें 3 कोल्ड कॉफी, 5 फ्लेवर्ड मिल्क और 10 कैंडी आइसक्रीम के अलावा श्रीखंड के 5 नए फ्लेवर्ड है। बाजार में सरस की एक आईसक्रीम की कीमत कम से कम 5 रुपए रखी गई है। उन्होंने बताया- इससे पहले भी जयपुर डेयरी ने नमकीन छाछ के कुछ नए वैरिएंट लॉन्च किए थे। इसका बाजार में अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। इसमें पुदीना और तड़का छाछ की डिमांड बहुत मात्रा में आ रही है।

राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर वैकेंसी

1 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, जून में होगी परीक्षा और नवंबर में आएगा रिजल्ट

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने नेशनल स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के 13 हजार 252 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आज से 1 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही यह सभी भर्तियां संविदा आधारित होंगी। जिसकी समय अवधि को सरकार द्वारा बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

जून में होगी परीक्षा, नवंबर में आएगा रिजल्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इन भर्ती परीक्षाओं में 1 मई तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 2 जून से 12 जून तक अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड द्वारा जून और जुलाई में ही भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी। इसके बाद 13 नवंबर तक सभी भर्तियों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा।

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु ने गद्दी पर बैठाया

मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच रस्म निभाई; पगड़ी दस्तूर हुआ, जगदीश मंदिर में किए दर्शन

राजस्थान की राजनीति

उदयपुर। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु डॉ. वागीश कुमार गोस्वामी ने बुधवार को गद्दी पर बैठाया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच यह रस्म निभाई गई। इसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत तमाम संत-महात्माओं का आशीर्वाद लिया।

गद्दी की पूजा-अर्चना कर विराजमान होने के बाद लक्ष्यराज सिंह ने श्रीएकलिंगनाथजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। धूणी दर्शन किए। इसके बाद अश्व पूजन किया। शाम को उन्होंने एकलिंगनाथजी मंदिर में दर्शन किए। यहां शोक भंग की रस्म निभाई गई। रात में पगड़ी का रंग पलटाई दस्तूर हुआ। आखिर में जगदीश मंदिर में दर्शन किए।

6. पॉइंट में समझिए गद्दी उत्सव की पूरी परंपरा...

1. सिटी पैलेस में सुबह हवन-पूजन से हुई शुरुआत

उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में सुबह करीब 9:30 बजे हवन-पूजन शुरू हुआ था। ओडिशा के डिप्टी सीएम और लक्ष्यराज सिंह के ससुर कनकवर्धन सिंह, जाने-माने कवि-एक्टर शैलेश लोढ़ा सहित तमाम लोग उदयपुर सिटी पैलेस में सुबह ही पहुंच चुके थे। सिटी पैलेस स्थित नौ चौकी महल के राय आंगन में सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनकर आए। लक्ष्यराज सिंह ने सफेद कपड़ों में विधि-विधान से गद्दी उत्सव की परंपरा निभाई। इस दौरान लक्ष्यराज के बेटे हरितराज सिंह ने संतों का आशीर्वाद लिया।

2. घोड़े की पूजा की, आरती उतारी

सिटी पैलेस के शंभू निवास में दोपहर करीब 3 बजे लक्ष्यराज सिंह ने बेटे हरितराज के साथ अश्व पूजन किया। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। मेवाड़ में राजतिलक या फिर गद्दी पर विराजने की रस्म के साथ ही अश्व पूजन की परंपरा भी निभाई जाती है।

मान्यता है कि अश्व को स्वामी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। युद्ध के समय अश्व भी अपने राजा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, जिसने हल्दीघाटी युद्ध में घायल होकर भी महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला था। इसलिए मेवाड़ का पूर्व राजपरिवार विशेषकर राजतिलक या गद्दी विराजने के अलावा विशेष त्योहारों पर भी अश्व पूजन करता है।

घोड़ा मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का ही होता है। पूर्व राजपरिवार की अश्वशाला सिटी पैलेस और शिकारबाड़ी में है। महाराणा करण सिंह ने 1620-1628 ईस्वी में घोड़ों का अस्तबल बनाया था। हालांकि मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार में अस्तबल की परंपरा 1500 साल से भी पुरानी है।

3. एकलिंगजी के दर्शन किए, शोक भंग की रस्म निभाई

शाम करीब 6 बजे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कैलाशपुरी स्थित एकलिंगनाथजी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद शोक भंग की रस्म निभाई गई, जिसमें पगड़ी का रंग भी बदला गया।

एकलिंगनाथजी मंदिर में दर्शन से पहले उन्होंने तालाब पूजन किया। कैलाशपुरी की महिलाओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जगह-जगह पुष्प वर्षा की गई। महिलाओं ने उनके स्वागत में धार्मिक गीत भी गाए।

4. हाथीपोल द्वार का पूजन किया

एकलिंगजी से आने के बाद रात करीब 7:30 बजे लक्ष्यराज सिंह उदयपुर शहर के हाथीपोल पहुंचे। यहां उन्होंने हाथीपोल द्वार का पूजन किया। इतिहास में यह शहर का मुख्य पोल हुआ करता था। जहां से शहर के अंदर एंट्री होती थी। पूजन के बाद आमजन ने लक्ष्यराज का पुष्प वर्षा और माला पहनकर स्वागत किया।

5. पगड़ी का बदला गया रंग

रात करीब 9 बजे सिटी पैलेस के दरबार हॉल में भाईपा और सरदारों का रंग पलटाई दस्तूर किया गया। सबसे पहले लक्ष्यराज सिंह के परिवारजन और रिश्तेदारों की पगड़ी का रंग बदला गया। लक्ष्यराज सिंह के ससुर और ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह ने इसकी शुरुआत कराई। इसके बाद लक्ष्यराज ने अपने रिश्तेदारों और समाज के प्रमुख लोगों को पाग भेंट की। पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ यह रस्म निभाई गई।

6. परिवार के साथ जगदीश मंदिर में दर्शन किए

रात करीब 10:15 बजे लक्ष्यराज सिंह ने जगदीश मंदिर में दर्शन किए। वे अपनी पत्नी निवृति कुमारी, बच्चे, ससुर और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ यहां पहुंचे थे।

बता दें कि लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च को हुआ था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब, 7 अप्रैल को पेश होंगे

नाबालिग लड़की की गुमशुदगी के मामले में नहीं हुई कार्रवाई; कहा- पुलिस ने लापरवाही बरती

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने देवीलाल गुर्जर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को 7 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता ने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को तलाशने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई के दौरान डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौत्तम अदालत में पेश हुई। उन्होंने इस मामले से जुड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। रिपोर्ट में कोर्ट के सामने आया कि पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद डेढ़ महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की।

नाबालिगों के मामले में गंभीर लापरवाही

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- पुलिस नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में गंभीर लापरवाही बरती है। मामले में भी एफआईआर दर्ज होने के बाद डेढ़ महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- अगर इस तरह के मामलों में पुलिस मामला दर्ज होने के दो-तीन दिन में ही कार्रवाई शुरू कर दे तो बच्चियों की रिकवरी बढ़ सकती है। ऐसे में डीजीपी कोर्ट में पेश होकर बताएं कि नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करती है।

परिजन चक्कर लगाते रहे, कार्रवाई नहीं हुई

याचिकाकर्ता के वकील नरेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा- परिजनों ने नाबालिग के अपहरण का मामला 5 फरवरी को प्रतापनगर थाने में दर्ज कराया था। परिजनों ने पड़ोस के गांव में रहने वाले युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने डेढ़ महीने तक कोई जांच नहीं की।

गुर्जर ने बताया- परिजन रोज थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब हाईकोर्ट में दायर याचिका पर नोटिस जारी हुए, तब पुलिस ने 10 मार्च को आरोपी के परिजनों के बयान दर्ज किए। यह बात आज कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई।

पर्यावरण परिषद में नई नियुक्ति: तराक मंगेश आरोलेकर बने गोवा प्रदेश अध्यक्ष

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद ईकाई (भारत) ने गोवा के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तराक मंगेश आरोलेकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका पदभार ग्रहण समारोह बुधवार को पणजी में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में परिषद के सेंट्रल डायरेक्टर लक्ष्मण लोहाना बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उनकी नियुक्ति परिषद के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी की अनुशंसा पर की गई है। लोहाना ने कहा कि नए अध्यक्ष के साथ मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध गोवा बनाने का प्रयास किया जाएगा।

परिषद का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही 'एक पेड़ मां के नाम' योजना को जन-जन तक पहुंचाना है।

युवाओं को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया।

हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इंटरव्यू पर रोक लगाई

200 पदों की भर्ती अटकी, आरपीएससी ने एग्जाम प्रकिया के बीच में बदले थे नियम

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर आयोजित हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है। इसमें बताया गया कि एग्जाम के बाद नियम बदलते हुए न्यूनतम अंकों में बदलाव किया था। जो गैर संवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में निर्धारित कर चुका है कि रुल्स ऑफ गेम का भी सिद्धांत है कि खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। आरपीएससी द्वारा बीच में नियम बदलने से हमारे हित प्रभावित हुए हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वहीं, सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा।

न्यूनतम अंकों में किया था बदलाव

एडवोकेट हरेन्द्र नील ने बताया कि विज्ञप्ति में भर्ती नियमों के तहत लिखित परीक्षा के दोनों पेपर (विषय और जीके) में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए पात्र माना जाना था। लेकिन कार्मिक विभाग ने 25 फरवरी 2025 को नियमों को संशोधित करते हुए न्यूनतम अंक 36 प्रतिशत कर दिए। जिसके बाद आरपीएससी ने विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए इस भर्ती परीक्षा में भी इसे लागू कर दिया।

'मैंने पहले ही कहा था उतना निवेश नहीं आ पाएगा': राइजिंग राजस्थान पर गहलोत बोले- उन्हीं से एमओयू करें जो फोन उठाएं

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा-मैंने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि जितना प्रचार कर रहे है उतना निवेश नहीं हो पाएगा।

दरअसल, झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को युवा कांग्रेस की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस फेयर में 170 से अधिक बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब भी मौजूद रहे।

बोले- 10-12 हजार करोड़ भी आते तो स्वागत करते

राइजिंग राजस्थान को लेकर पूर्व सीएम ने कहा- भाजपा की सरकार ने खूब प्रचार किया था। विदेशों के दौरे किए और 33 लाख करोड़ के एमओयू होने के दावे किए। अगर उनमें से 10- 12 हजार करोड़ भी आते है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि निवेश कुछ आया।

लेकिन, अब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे, ईमेल का जवाब नहीं दे रहे है। आगे से अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं से एमओयू करे, जो फोन उठाए।

पूर्व सीएम बोले- मैंने तो पहले से ही इसकी आशंका व्यक्त कर दी थी कि जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है उतना निवेश नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार अमीर दोस्तों का ही भला कर रही है।

बोले- गली-गली लगने चाहिए रोजगार मेले

वहीं रोजगार मुद्दे पर भी पूर्व सीएम गहलोत ने कहा- केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की सरकारों ने युवाओं से रोजगार के खूब बड़े-बड़े वादे किए लेकिन रोजगार नहीं दिया। उन्होंने युवा कांग्रेस के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के संदेश को अमली जामा पहनाया है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. मैं समझता हूं कि ऐसे रोजगार मेले गली गली में लगने चाहिए। बड़ी-बड़ी कंपनियां आई हैं और लोगों को हाथों-हाथ रोजगार मिल रहा है।

इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट कैंडिडेट को दिया जॉइनिंग लेटर

रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक के बेरोजगार युवाओं का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट उम्मीदवारों को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। आयोजकों का दावा है कि पहले चरण में करीब 2000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कृष्णा अल्लावारू ने कहा- केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही है। हमने युवाओं को रोजगार देने की पहल राजस्थान से शुरू की है और जिस तरह का रिस्पांस युवाओं का मिला है उसको देखते हुए हम अब हर राज्य में इसे लागू करेंगे। का दावा है कि शाम 5 बजे तक ढाई से तीन हजार युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। अब जिला और ब्लॉक लेवल पर भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे।

उन्होंने कहा- आगे संभाग और विधानसभा स्तर पर भी ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे। जो काम सरकारों को करना चाहिए, वह अब युवा कांग्रेस को करना पड़ रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर पूछे गए सवालों पर नेताओं ने कहा कि बिल पेश होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जवाब देगा।

प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया का दावा है कि शाम 5 बजे तक ढाई से तीन हजार युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। अब जिला और ब्लॉक लेवल पर भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे।

सुबह 8 बजे से हुए रजिस्ट्रेशन

इससे पहले राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 8 बजे से ही युवा बेरोजगारों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। कैंपस में बड़ी-बड़ी कंपनियों के कियोस्क लगाए गए जहां पर युवाओं के साक्षात्कार हुए और उसके बाद उन्हें जॉइनिंग लेटर दिए गए।

जॉब फेयर में 186 कंपनियों में कुछ कंपनी के नाम जेसीबी, अमेजन, फ्लिप कार्ट, केस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाईफ,, महिंद्रा, जेप्टो, जस्ट डायल, एमआरएफ, पीवीआर जैसे अनेक निजी कंपनी आएंगी और युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार दे रही है।

नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में नौ दिवसीय राजस्थान उत्सव-2025 का हुआ समापन, मेले में आर्टिजंस की हुई 50 लाख की ज्यादा की बिक्री महिलाओं के हुनरबंद हाथों से निर्मित उत्पादों का हुआ मेले में प्रर्दशन

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। दिल्लीवासियों सहित अप्रवासी राजस्थानियों के दिलों पर राजस्थानी कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और खानपान की यादें छोड़कर नौ दिवसीय राजस्थान उत्सव मेले का बुधवार को समापन हुआ। राजस्थान उत्सव में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा राजस्थानी संस्कृति और लोक कला को समेटे हुए हस्तकला निर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया था। उत्सव के दौरान राजस्थान के विभिन्न अंचलों की महिला आर्टिजंस ने लगभग 60 स्टॉलों पर अपनी कला का सजीव प्रदर्शन कर दर्शकों और खरीददारों को अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थान उत्सव में राजीविका की तरफ से मेले का संचालन देख रहे श्री रमेश कुमार ने बताया कि मेले में आर्टिजंस के स्टॉल्स पर 50 लाख से ज्यादा की अच्छी बिक्री हुई है। इन स्टॉल्स पर राजस्थान की महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, कपड़े, आभूषण, जैविक उत्पाद, पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन इत्यादि बिक्री के लिए लगाए गए, जिससे आगंतुकों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तकला का बखूबी परिचय हुआ। रमेश ने बताया कि राजीविका की महिलाओं द्वारा लगाए गए इन स्टॉल्स पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने से न केवल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिला बल्कि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उत्सव में आने वाले लोगों ने इन हस्तनिर्मित वस्तुओं को खूब सराहा और बड़ी मात्रा में खरीदारी भी की। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में नौ दिवसीय राजस्थान उत्सव-2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया था। उत्सव में इस वर्ष भी पेंटिंग प्रतिस्पर्धा, मेहंदी प्रतिस्पर्धा, गोलगप्पा खाने की प्रतिस्पर्धा के साथ ही पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। जिसमें अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को सांत्वना पुरूस्कार से सम्मानित किया गया।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक, राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री में देश में अव्वल- राजस्व मंत्री

राजस्व मंडल के नवाचारों से मिल रही आमजन को राहत

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

मीणा बुधवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सीमाज्ञान,आपसी सहमति से बंटवारा, भू-रूपांतरण के लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सीमाज्ञान के लिए संचालित ई-धरती पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का व्यवस्थित और समयबद्ध निस्तारण कर अधिकारी जीरो पेंडेंसी पर कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक में मीणा ने राजस्व मंडल एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त न्यायालयों, जिला कलक्टर न्यायालयों के लंबित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक वर्षों से लंबित राजस्व वादों का प्रत्येक न्यायालय चिन्हित कर प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू प्रदेश के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समस्त जिला कलेक्टर्स को राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के भू आवंटन, नामांतरण दर्ज करने, संपरिवर्तन आदि प्रकरणों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपनिवेशन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग दिनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कलेक्टर पटवार मंडल स्तरों पर डोर-टू-डोर रजिस्ट्रेशन चालू रखें, जिससे फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भू रूपांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल द्वारा किये गए नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल में प्रतिदिन 15 सबसे पुराने मामलों की सुनवाई अनिवार्य की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि न्यायिक कार्य के लिए दो पारियों की शुरुआत की गई है, इससे राजस्व न्यायालयों की कार्यकुशलता तथा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण प्रतिशत में सकारात्मक वृद्धि हुई है। विचाराधीन वाद जिसमें सरकार पक्षकार है, इनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं आयुक्त, उपनिवेशन वीसी के माध्यम से तथा निबंधक राजस्व मंडल, भू प्रबन्ध आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चिकित्सा मंत्री ने समीक्षा कर दिए निर्देश, मौसमी बीमारियों से बचाव की हो पुख्ता तैयारियां

अलर्ट मोड में रहें अधिकारी, नियमित रूप से करें निरीक्षण –जांच, दवा एवं उपचार का हो माकूल प्रबंध

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी एवं हीटवेव की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों में अधिकारी अलर्ट मोड में रहते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। किसी भी चिकित्सा संस्थान में जांच, दवा एवं उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, राज्य स्तर से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। साथ ही, संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक रूप से निरीक्षण करें ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें।

जहां स्टाफ की कमी, वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें

खींवसर ने सभी जिलों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां भी डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। स्थानीय स्तर पर नियमानुसार संविदा आधार पर चिकित्सक या अन्य चिकित्साकर्मियों की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने गुरूवार दोपहर तक सभी जिलों से चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की स्थिति की विस्तृत जानकारी भिजवाने के निर्देश दिए।

जरूरी संसाधनों की खरीद एवं मेंटीनेंस समय पर हो

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में पंखे, कूलर, एसी आदि की कमी की शिकायत नहीं आए। समय रहते जरूरी संसाधनों की खरीद एवं मेंटीनेंस सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए तात्कालिक आवश्यकतानुसार आरएमआरएस में उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए। साथ ही, दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से भी सहयोग लिया जा सकता है। खींवसर ने कहा कि जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर उनका सुचारू संचालन किया जाए। सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाएं पुख्ता हों। एम्बुलेंस की क्रियाशीलता एवं उसमें सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

ट्रोमा सेंटर व एफआरयू के रिक्त पदों को जल्द भरेंगे

खींवसर ने सभी जिलों में ट्रोमा सेंटर्स एवं एफआरयू के सुचारू संचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बचाने में ट्रोमा सेंटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इन सेंटर्स में आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर इनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित कर रही है। जहां भी आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरणों की कमी के कारण ट्रोमा सेंटर व एफआरयू का संचालन प्रभावित हो रहा है, वहां जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाएगा।

प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ तैयारियां जारी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ समय रहते आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार की जरूरी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक या अन्य स्टाफ की कमी है, वहां जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर पदों को भरा जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हों। दवाओं की समयबद्ध रूप से समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अधिकारी नियमित रूप से व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करें।

राजस्थान को देश का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश बनाएं, हर गांव प्रतिदिन साफ हो यह हमारा संकल्प हो -शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस साल राजस्थान को देश का सबसे स्वच्छ ग्रामीण प्रदेश बनाने का लक्ष्य पूरा करते हुए हमें ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि हर गांव प्रतिदिन साफ हो यह हमारा संकल्प होना चाहिए। गांवों में प्रतिदिन झाड़ू लगे, नालियों की सफाई हो और घर-घर से कचरा संग्रहण किया जाए, इसके लिए ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को 80 हजार से लेकर 2 लाख 50 हजार रूपये प्रति माह तक सफाई के लिए पैसा मिलता है उसका समुचित उपयोग करते हुए गांवों को स्वच्छ रखें।

दिलावर बुधवार को कोटा जिले के केडीए ऑडिटोरियम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कोटा संभाग के कोटा एवं बारां जिले की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को एक हजार टीमें गठित कर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर वहां सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर जिन ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाई जाएगी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिकारी गलत आंकड़ें प्रस्तुत नहीं करें बल्कि जो वास्तविकता हो उसे सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि आंकड़ों एवं धरातल की वास्तविकता में अंतर नहीं हो। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था के लिए उपलब्ध पैसा किसी अन्य कार्य के लिए काम में नहीं लिया जाए। उन्होंने जिला परिषद सीईओ, बीडीओ, एईएन एवं अन्य अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के सफाई कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी निरीक्षण के दौरान यह देखें कि गांवों में प्रतिदिन सफाई हो, घर-घर कचरा संग्रहण किया जाए एवं नालियों की पर्याप्त रूप से सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि घरों से एकत्र किया जाने वाला कचरा तय जगह पर डाला जाए।

दिलावर ने सीईओ जिला परिषद कोटा एवं बारां से पूछा कि उन्होंने किन-किन ग्राम पंचायतों में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद एवं खैराबाद के बीडीओ से ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण एवं गांवों में रात्रि विश्राम के बारे में पूछा। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था के रजिस्टर का सही तरीके से संधारण किया जाए और उसी के आधार पर संबंधित ठेकेदार को भुगतान किया जाए।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु आवासहीन परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 हजार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु परिवारों को पट्टा देने का लक्ष्य रखा गया है। जिन परिवारों को 2 अक्टूबर 2024 को पट्टे दिए गए थे उनकी रजिस्ट्री भी समय पर कराई जाए और उन्हें मौके पर जाकर कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने इन परिवारों को पीएम आवास योजना की सूची में शामिल कर उनके मकान बनवाने के भी निर्देश दिए।

अन्नपूर्णा योजना में गरीब को 8 रूपये में भरपेट भोजन

दिलावर ने अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति को आठ रूपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ठंडी रोटी खिलाने अथवा आठ रूपये से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही की जाए एवं अनियमितता करने वाली संस्थाओं को हटाया जाए।

बर्तन बैंक के लिए हुआ एमओयू

कार्यक्रम में सांगोद पंचायत समिति के सावनभादौ गांव में बर्तन बैंक संचालन के लिए नारायणी स्वयं सहायता समूह के साथ एमओयू किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत मंडाना में शीतला माता स्वयं सहायता समूह के साथ बर्तन बैंक संचालन के लिए एमओयू किया गया। इसके तहत स्टील के बर्तनों के 400 सेट दिए गए ताकि सामूहिक भोजन के अवसर पर डिस्पोजल का कम से कम उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण किया जा सके और गौ माता को प्लास्टिक खाने से बचाया जा सके। प्रति बर्तन सेट 3 रूपये किराया निर्धारित किया गया है जो स्वयं सहायता समूह द्वारा लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा के तहत पूरे प्रदेश में एक हजार ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए जाने हैं जिसमें प्रथम चरण में कोटा जिले में 20 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक बनाए जाएंगे।

एसबीएमजी ऐप लॉन्च

कार्यक्रम में स्वच्छता मॉनिटरिंग के लिए एसबीएमजी राजस्थान ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप एन्ड्रॉयड एवं आईओएस दोनों वर्जन पर काम करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति सिटीजन डेशबोर्ड पर जाकर गंदगी पड़ी होने या कचरा पड़ा होने की शिकायत फोटो खींचकर करेगा जिस पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी एक्शन लेते हुए वहां सफाई करवाकर शिकायत निस्तारण की सूचना ऐप पर अपलोड करेंगे। इस ऐप पर बीडीओ, एसीईओ, सीईओ एवं राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक सलोनी खेमका एवं संयुक्त निदेशक अशोक पारीक ने स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं नवाचारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण, गीला एवं सूखा कचरा अलग करने, सड़क, बाजार आदि में झाड़ू लगाने, नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई के संबंध में बीएसआर दरें तय कर दी गई हैं। इससे स्वच्छता संबंधी कार्यों में एकरूपता लाने तथा निविदा आमंत्रण में आसानी होगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के माध्यम से स्वच्छता कार्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं निविदा शर्तों के बारे में भी जानकारी दी। उपायुक्त पंचायती राज इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था के मामले में किसी तरह की लापरवाही बरती जाएगी। उन्होंने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु श्रेणी के आवासहीन परिवारों को पट्टा वितरण की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को अभियान चलाकर एक साथ 17 हजार 500 पट्टे वितरित किए गए थे। बैठक में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, किशनगंज विधायक ललित मीणा सहित कोटा एवं बारां जिले के उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, बीडीओ, एईएन, सहायक लेखाधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित पंचायती राज महकमे से जुड़े कार्मिक उपस्थित थे।

संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर के पूनियों की प्याऊ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया औचक निरीक्षण, प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध - संसदीय कार्य मंत्री

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को प्राथमिक जोधपुर जिले के स्वास्थ्य केन्द्र पूनियों की प्याऊ का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जनरल ओपीडी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, लेबोरेटरी कक्ष, लेबर वार्ड,टीकाकरण कक्ष,पंजीकरण रजिस्टर एवं दवाओं के स्टॉक का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

3500 करोड़ रुपये के 'मा कोष' का होगा गठन

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपये के 'मा कोष' का गठन किया जाएगा।

केरू में बनेगा ट्रॉमा सेंटर

पटेल ने कहा क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सौगातें मिली हैं जिसमें केरू में ट्रॉमा सेंटर क्षेत्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

सभी कार्मिकों को समय पर अस्पताल में उपस्थित रहने के निर्देश

संसदीय कार्य मंत्री ने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं।

आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

पटेल ने रजिस्ट्रेशन काउंटर,आवश्यक सामग्री एवं शुद्ध पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो,चिकित्सक इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया।

बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं, अधिकारी 'माइक्रो प्लानिंग' कर तय समयावधि में घोषणाओं को धरातल पर उतारें -निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी किया मोटिवेट

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण 'माइक्रो प्लानिंग' कर घोषणाओं को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर श्री अग्रवाल ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय 'अम्बेडकर भवन' स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के जरिए बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान निदेशालय सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की तो कम प्रदर्शन करने वाले जिलों कों मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा घोषणाओं की उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है, ऐसे में अधिकारीगण किसी भी स्तर पर कोर-कसर नहीं छोडें। अग्रवाल ने कहा किया बजट 2025-26 घोषणाओं की क्रियान्विति से पूर्व पिछले वर्ष की जो भी बजट घोषणाएं अपूर्ण हैं, उन्हें सबसे पहले पूरी करने पर जोर दें। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिन्हीकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार देने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयंसिद्धा आश्रम, देवनारायण आवासीय योजना, कामकाजी महिला आवास योजना, बेघर वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने, प्रदेश के एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना% से जुड़े आवेदनों की जांच और सत्यापन कार्य आगामी 3 दिवसों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन से शेष मामलों में अधिकारियों को शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नवाचार करते हुए ओटीपी और एप के जरिए वेरिफिकेशन करवाएं। उन्होंने 7 और 8 अप्रेल को देहरादून में होने वाले चिंतन शिविर तथा 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्री केसरलाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जांगिड़, अतिरिक्त निदेशक श्री हरिसिंह मीणा, अतिरिक्त निदेशक श्री अरविंद सैनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात

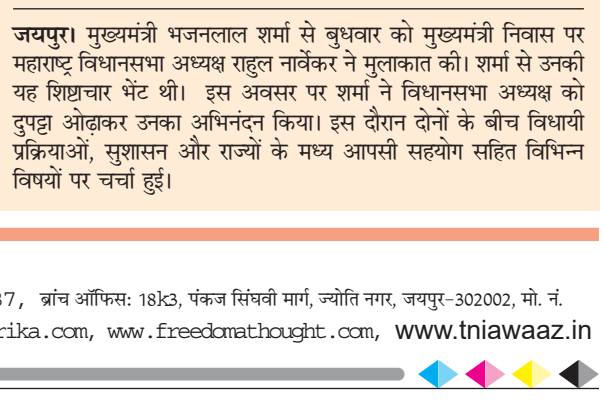

राजस्थान की राजनीति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुलाकात की। शर्मा से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों के बीच विधायी प्रक्रियाओं, सुशासन और राज्यों के मध्य आपसी सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक एवं संपादक रमाकांत गोस्वामी द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, पीपलेश्वर मंदिर के पीछे, नला मौहल्ला,दौसा (राजस्थान)-303303 से प्रकाशित किया। संपादक: रमाकान्त गोस्वामी, कार्यकारी संपादक भूपेंद्र कुमार शर्मा, स्थानीय संपादक: संजय लाटा (अवैतनिक) आरएनआई नं. RAJHIN/2012/43137, ब्रांच ऑफिस: 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल- tniawaz.news@gmail.com, Group of Sites- www.hpnews.in, www.right2action.in, www.jaipurtak.com, www.dharmjagran.com, www.hindustanpatrika.com, www.freedomathought.com, www.tniawaaz.in